मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 19 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 7 – 13 मई 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

बेटी बचाओ, नारा नहीं, बेटियों को भाजपाई धमकी है? 3

विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन: अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग का हितरक्षक..........................5

मई दिवस जोर–शोर से मनाया गया

मजदूरों का संकल्प: मजदूर विरोधी भाजपा सरकार को करेंगे अपदस्थ

देश भर में मजदूरों और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों, समर्थकों के साथ 1 मई 2023 को जोर–शोर से मई दिवस मनाया गया और नरेंद्र मोदी नीत मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी आरएसएस–भाजपा सरकार को केंद्र से हटाने की प्रतिज्ञा ली गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा, जो कि उस दिन चेन्नई में थे उन्होंने तमिलनाडु भाकपा राज्य समिति के कार्यालय बालम इल्म के आँगन में लाल झण्डारोहण किया। सभा को संबोधित करते हुए डी राजा ने संक्षेप में देश की परिस्थिति का वर्णन किया और उन्होंने 2024 के आम चुनावों में भाजपा सरकार को हटाने के लिए संघर्ष तेज करने की अपील कामरेडों से की।

पार्टी के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय अजय भवन में भाकपा राष्ट्रीय महासचिव सय्यद अजीज पाशा ने लाल झण्डारोहण किया। मई दिवस के मौके पर उपस्थित कामरेडों को संबोधित करते हुए अजीज पाशा ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि 1 मई 1866 के दिन शिकागो के मजदूरों ने आठ घंटे काम, आठ घंटे आराम और आठ घंटे दिल बहलाव की मांग पर हड़ताल शुरू की थी। इस आंदोलन के कारण आठ मजदूरों की गिरफ्तारियाँ हुई, उसमें से चार को मौत की सजा दी गई, दो की जेल में मृत्यु हो गई और दो को आजीवन कारावास की सजा दी गई । उन्होंने यह भी बताया कि भारत में एटक की एक यूनियन ने 1923 में वर्तमान तमिलनाडु में मई दिवस मनाया था।

हमारे विशेष संवाददाता

दिल्ली

दिल्ली में चांदनी चौक के टाउन हॉल में एक जनसभा आयोजित की गई। नारों और क्रांतिकारी गीतों की गूंज दूर–दूर तक फैल गई थी।

मई दिवस की सभा को एटक महासचिव अमरजीत कौर, एटक सचिव आर पराशर, एटक उपाध्यक्ष सुचेता डे, सीटू राज्य महासचिव अनुराग कश्यप, टीयूसीसी सचिव नारायण सिंह, सेवा से सुभद्रा और आईसीटीयू से नरेंद्र ने संबोधित किया। एटक जत्थे का नेतृत्व सतीश कुमार, मुकेश कश्यप और विजय तिवारी दिल्ली राज्य एटक के महासचिव और उप महासचिव ने किया।

अमरजीत कौर ने अपने संबोधन को शुरू करने से पहले सभा में उपस्थित सभी साथियों से शिकागो के शहीदों और इस संघर्ष को जारी रखने में जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखने के लिए कहा।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग ने आठ घंटे के कार्य दिवस पर आवाज उठाई थी। विरोधाभास है कि नरेंद्र मोदी सरकार समय को पीछे लौटाने की सभी कोशिशें कर रही है और उनके जोर देने पर कर्नाटक सरकार ने कारखाने अधिनियम में संशोधन किया है, इससे काम करने का समय आठ घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में भी इसी तरह का एक विधेयक पारित किया गया था, लेकिन ट्रेड यूनियनों और सत्तारूढ़ पार्टी के सहयोगियों द्वारा संयुक्त रूप से विरोध करने पर, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने संशोधन वापस ले लिया।

अमरजीत ने कहा कि सरकार मजदूर वर्ग के कड़े विरोध के कारण श्रम संहिता को लागू नहीं कर सकी और सरकार अपने एजेंडे को टुकड़ों में आगे बढ़ा रही है। भारतीय और विदेशी कंपनियों के पक्ष में काम करने वाली सरकार असमानता में वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, अभूतपूर्व बेरोजगारी और भूख फैला रही है। सार्वजनिक क्षेत्र को बिक्री के लिए रखा है, लघु क्षेत्र और खुदरा व्यापार संकट में हैं, जबकि जीवन की अनिश्चितता का होना निश्चित होता जा रहा है।

उन्होंने धार्मिक, सांस्कृतिक, जाति और भाषाई आधार पर नफरत फैलाने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार जारी बयानों से सावधान रहने के लिए कहा। सत्तारूढ़ पार्टी की नफरत फैलाने वाली राजनीति देश के संविधान में वर्णित लोगों के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। कामकाजी वर्ग को हमारे संविधान के मूल मूल्यों जैसे कि असहमति के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विभिन्न विश्वासों और सांस्कृतिक मूल्यों के सम्मान की रक्षा करने के लिए अगुआ दस्ते में होना चाहिए।

उन्होंने मजदूर वर्ग का आह्वान करते हुए कहा कि वे 30 जनवरी, 2023 को मजदूरों के नेशनल कन्वेन्शन के निर्णयों को लागू करें, ताकि आरएसएस–भाजपा सरकार की राष्ट्र विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए जनगण के बीच व्यापक अभियान चलाया जा सके और 2024 में जनगण इस क्रूर शासन की वापसी परेड का आदेश दे सके।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वी दिल्ली के जिला कार्यालय में मई दिवस के अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ साथी रतन कुमार शर्मा ने झंडा फहराया।

इस अवसर पर अखिल भारतीय नौजवान सभा दिल्ली राज्य सचिव शशि कुमार गौतम, रतन कुमार शर्मा, और डॉ. केहर सिंह सचिव, पूर्वी दिल्ली व राज्य सचिवमंडल सदस्य ने अपने विचार रखे।

पानीपत (हरियाणा)

मई दिवस के अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं एटक ने 1 मई को संयुक्त रुप से पानीपत की देशराज कालोनी, 11 वार्ड, गणेश नगर, सैनी कालोनी में दर्जन भर के करीब नुक्कड मीटिंग आयोजित की। नुक्कड़ मीटिंगों को भाकपा के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप, जिला सचिव पवन सैनी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य राम रतन एडवोकेट, एटक नेता अशोक पंवार, किसान नेता माम चंद सैनी, सेवा सिंह मलिक आदि ने सम्बोधित किया। वक्ताओं ने मई दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि आज से 137 वर्ष पहले आज ही के दिन अमेरिका के शिकागो शहर में हजारों मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर हड़ताल की और प्रर्दशन किया। इन शांतिपूर्ण प्रर्दशनकारियों पर तत्कालीन अमेरिका सरकार की पुलिस ने अंधाधुंध लाठीचार्ज किया और गोलियां बरसाते हुए कई मजदूरों को शहीद कर दिया। किसान मजदूर नेताओं ने कहा कि कालांतर में दुनिया भर में कानूनी तौर पर 8 घंटे कार्यदिवस होने के साथ साथ मजदूरों की भलाई के लिए अनेक कानून बनाए गये लेकिन आज की भाजपा सरकार इन सभी हक अधिकारों पर हमले करके मजदूरों को गुलाम बनाना चाहती है। हमें एकजुट होकर सरकार की जनविरोधी, देश विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करना

शेष पेज 15 पर...

संपादकीय

झूठ के कारखाने से आई एक फिल्म

हर आए दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार प्रचार के अपने फासिस्टी कौशल को और अधिक बढ़चढ़ कर दिखाता रहता है। मुसोलिनी और हिटलर से सीख लेकर और समय एवं स्थान के अनुसार उस चीज को अद्यतन बनाते हुए कभी–कभी वे अपने आकाओं से भी आगे निकल जाते हैं। 1935 में एक फिल्म प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन करते हुए बेनिटो मुसोलिनी ने एक सूत्र–वाक्य दिया था कि ''सिनेमा सबसे ताकतवर हथियार है''। उसके पदचिन्हों पर चलते हुए एडॉल्फ हिटलर और उसके प्रचार मंत्री जोसेफ गोयबल्स ने भी उनकी रूचि और रूझान के अनुसार फिल्में बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं को पटाने की कोशिश की। आरएसएस–भाजपा के सत्ता में आने के शुरूआती दिनों से ही भारत में देखा जा रहा है कि अपने राजनैतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वे कला और साहित्य को इस्तेमाल करने की संभावनाओं का उपयोग कर रहे हैं। पुणे में एफटीआईआई (फिल्म एंड टेलीविजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया) में हुए घटनाक्रमों ने दिखाया कि संस्कृति के क्षितिज को दूषित करने के लिए वे इस कदर हठपूर्वक और सुविचारित तरीके से काम कर रहे हैं। इस सबके पीछे कला या सौन्दर्यबोध को प्रोत्साहन देना उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा। इसके बजाय उनका उद्देश्य रहा है कि देश में झगड़ा–फसाद और नफरत के बीज बोये जाएं। ''कश्मीर फाईल्स'' नामक फिल्म में जो जहरीला नैरेटिव था वह सिनेमा के माध्यम से जनता के दिमागों को प्रभावित करने की इसी चाल का हिस्सा था। इस तरह के खतरनाक खेल खेलते–खेलते अब वह ''द केरल स्टोरी'' नामक फिल्म लेकर आए हैं जो इस सिलसिले का सबसे जहरीला खेल है।

उनकी ''द केरल स्टोरी'' केरल की वास्तविक कहानी नहीं है। केरल की वास्तविक कहानी प्यार और सम्मान से रची–बसी है जिसे विभिन्न आस्थाओं से संबंध रखने वाले केरल के लोगों ने पीढ़ियों के दौरान ह्रदयंगम किया है। केरल की इसी वास्तविक कहानी को श्रेय जाता है कि सभी मानव विकास सूचकांकों में यह राज्य शीर्ष स्थान पर है। केरल के लोग इस वास्तविक कहानी के निर्माता हैं और धर्म एवं जाति के भेदभाव भुलाकर उन्होंने हमेशा भाईचारे के संबंध बनाए रखे हैं। इन महान लोगों ने धार्मिक चरमपंथी तत्वों को, चाहे वे हिन्दू हों, मुस्लिम हों या ईसाई हों, हमेशा अपने दिन–प्रतिदिन के जीवन से दूर ही रखा है। केरल के लोगों ने उनकी राजनीतिक पार्टियों को भी राज्य में जरा–सी भी जगह नहीं दी। यही कारण है कि आरएसएस–भाजपा ने जनता के प्रति प्रतिशोधपूर्ण भावना के साथ ''द केरल स्टोरी'' के नाम से एक अवास्तविक एवं काल्पनिक केरल को दिखाने के लिए गढ़ा है।

''द केरल स्टोरी'' नामक यह फिल्म पूरी तरह निराधार दावों, फर्जी खबरों और इस्लामभीति (इस्लामोफोबिया) पर आधारित है जिसका इरादा असली केरल की छवि को दाग लगाना और लोगों की बीच धार्मिक उन्मादी आधार पर फूट डालना है। इस फिल्म के निर्माताओं ने पहले दावा किया कि उन्होंने ऐसी 32,000 औरतों की कहानी का पता लगाया है जिन्हें धर्मान्तरण के लिए मजबूर किया गया या प्रलोभन देकर उनका धर्मान्तरण किया गया और बाद में वे आईएसआईएस में शामिल हो गई। जब लोगों और सच को प्यार करने वाले लोगों ने उनकी इस हास्यास्पद अतिशयोक्तिपूर्ण संख्या पर सवाल उठाया तो उनकी सिट्टी–पिट्टी गुम हो गई और उन्होंने संख्या को घटाकर 32,000 की जगह सिर्फ 3 कर लिया। इससे पता चलता है कि आरएसएस मार्का ''द केरल स्टोरी'' कितनी खोखली और झूठी है।

फिल्म के ट्रेलर में केरल के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयानों को गलत तरीके से उद्धृत किया गया है, उनकी गलत व्याख्या की गई है। वी.एस.अच्युतानंद द्वारा दिए गए बयान का मलयालम से अंग्रेजी में गलत अनुवाद किया गया और फिर उसका इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय की निंदा करने के लिए किया गया है। इसी प्रकार ओमेन चंडी ने धर्मान्तरण के किन्ही वार्षिक आंकड़ों का कभी जिक्र नहीं किया और न ही उन्होंने कभी महिलाओं के आईएसआईएस में शामिल होने या जबरन धर्मान्तरण का जिक्र किया। यह साफ है कि कुछ विश्वसनीयता पाने और जनता को गुमराह करने के लिए फिल्म में दोनों मुख्यमंत्रियों के बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। आरएसएस के पे–रोल पर काम करने वाले कुछ मीडिया और यूट्यूब चैनलों ने भी केरल के खिलाफ इसी तरह का दुष्प्रचार शुरू किया। केरल के लोगों ने राज्यों को बदनाम करने की इस राजनीति–प्रेरित कोशिश का एक स्वर में विरोध किया है।

यह फिल्म महिलाओं के इस्लाम में धर्मान्तरण के एक तरीके के तौर पर तथाकथित ''लव जेहाद'' को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। परंतु ''लव जेहाद'' एक आधारहीन इस्लामभीतिक षडयंत्र सिद्धांत है जिसका मकसद ध्रुवीकरण है। जो लोग इसका हल्ला करते हैं वे इसके बारे में कभी भी रत्तीमात्र भी सबूत सामने नहीं ला सके। अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रालय में राज्य मंत्री एस.जी. किशनरेड्डी ने 5 फरवरी 2020 में संसद को बताया था कि ''लव जेहाद'' के किन्हीं भी मामलों की कोई रिपोर्ट नहीं हैं। संसद में स्वयं भाजपा सरकार द्वारा इस सिद्धांत को खारिज किये जाने के बावजूद आरएसएस की झूठ फैक्टरी लोगों को इस अविश्वसनीय सिद्धांत में विश्वास कराने की दिनरात कोशिश करती रहती है।

इसी प्रकार, भारत सरकार एवं रणनीतिक स्रोतों के अनुसार, भारत के जो लोग आईएसआईएस में लड़ाकों के तौर पर शामिल हुए, उनकी संख्या 200 से अधिक नहीं इससे साफ जाहिर है कि ''द केरल स्टोरी'' जिस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है वह झूठ पर एवं तथ्यों को तोड़ने–मरोड़ने पर आधारित है और उसका लक्ष्य नफरत फैलाना है। यह केरल में खासतौर पर और सामान्यतः देश में सांप्रदायिक भाईचारे के लिए अत्यंत खतरनाक और नुकसानदेह बात है।

अब महत्वपूर्ण सवाल इसकी जिम्मेदारी का है। यदि काल्पनिक और फर्जी बातों को तथ्य के तरह पेश किया जाए तो कौन जिम्मेदार होना चाहिए? यदि भ्रामक एवं झूठी बातों को सच के तौर पर दिखाया जाए और उससे मन–मुटाव और झगड़े पैदा हों तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होना चाहिए? यह सच है कि आरएसएस द्वारा संचालित वर्तमान केंद्र सरकार हमारे संविधान और उसमें प्रतिष्ठापित मूल्यों का सम्मान नहीं करती। इसके अलावा उन्हें सत्य के संबंध में नैतिक तौर पर कोई चिंता भी नहीं है। तो भी हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के संबंध में लोगों को शिक्षित करने में एक लोकतांत्रिक राजशासन को एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना होता है और सरकार यह जागरूकता पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि फर्जी खबरों और नफरतभरे प्रचार को सच ना माना जाए। यदि भाजपा सरकार इस जिम्मेदारी से आंख चुरा रही है तो इसका अर्थ है कि उसकी निष्ठा आरएसएस विचारधारा में है, भारतीय संविधान में नहीं। हमारे देश का संकट यह है कि केंद्र सरकार पूरी तरह भाजपा के चुनावी तंत्र में बदल चुकी है। कर्नाटक चुनावों से पहले ''द केरल स्टोरी'' जनता का ध्रुवीकरण करने के लिए एक अन्य मंच है। यह देश के लिए एक खतरनाक स्थिति है, कैप्टन जहाज को डुबोने की अनवरत कोशिश कर रहा है।

जब सरकार ही अपने संवेधानिक अधिदेश से पीछे हट रही है तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि तथ्यों और वैज्ञानिक जांच की भावना के जरिये लोगों को इन विषयों के बारे में जागरूक किया जाए। अनेक लोगों ने यह विचार करते हुए कि इस फिल्म के पीछे एक घृणित योजना चल रही है, इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है जो समझ में भी आती है। परंतु जनता के विभिन्न तबकों की राय है कि प्रतिबंध लगाना इस समय इस मामले में शायद समुचित कदम न हो। हमें जनता के सामने तथ्यों को ले जाना चाहिए और उन्हें राजनीतिक प्रचार और सच के बीच अंतर करने के संबंध में शिक्षित किया जाना चाहिए। जनता के साथ संबंधों को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि कोई भी प्रचार और दुर्भावनापूर्ण काल्पनिक कथा उनके बीच में फर्क न डाल सके। शिक्षा और एकजुटता आरएसएस की झूठ की फैक्टरी के खिलाफ सबसे अधिक कारगर हथियार हैं। सच की विजय के लिए लोगों को एकताबद्ध हो उठ खड़े होना होगा।

एप्सो गुजरात का शान्ति आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान

अहमदाबादः लंबे समय के बाद गुजरात राज्य में एप्सो का गठन किया गया। 30 अप्रैल को एप्सो का गुजरात राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में विभिन्न जिलों के सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता कांग्रेस के दिग्गज नेता और जाने–माने समाजसेवी महेंद्र पटेल ने की। सम्मेलन का उद्घाटन विश्व शान्ति परिषद के अध्यक्ष और एप्सो के अध्यक्षमंडल सदस्य पल्लब सेनगुप्ता ने किया। समाज के विभिन्न हिस्सों से आने वाले दूसरे वक्ताओं ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। पल्लब सेनगुप्ता ने अपने संबोधन में अस्सी के दशक में गुजरात में एप्सो की भूमिका को याद किया और सम्मेलन में भाग लेने वालों से एक बहुत ही जटिल अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्थितियों से निपटने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने का अनुरोध किया। रूस–यूक्रेन युद्ध पर विचार–विमर्श करते हुए, उन्होंने जारी युद्ध को रोकने और कूटनीतिक और शांतिपूर्ण तरीकों से सभी समस्याओं को सुलझाने की मांग के एप्सो के स्टैंड के बारे में बताया। इस संबंध में, उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय लोगों के दोहरे मापदंड को भी उजागर किया, जो किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन रूस को हराने तक युद्ध जारी रखना चाहते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों के बारे

में, वह भारतीय संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए केंद्र और विभिन्न राज्यों में वर्तमान शासन के खिलाफ एक व्यापक जन गठबंधन बनाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। दूसरे वक्ताओं ने भी लगभग इसी सुर में आनी बाते रखीं और गुजरात में एप्सो की मजबूत नींव रखने को समय की जरूरत बताया। सम्मेलन में, रूस–युक्रेन युद्ध, भारतीय संविधान की रक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव पर तीन प्रस्ताव पारित किये गये। सम्मेलन में 41 सदस्यीय राज्य समिति का चुनाव किया गया, जिसमें से 17 सदस्यों को पदाधिकारी चुना गया। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. अतुल पाठक को एप्सो के राज्य अध्यक्षमंडल का चैयरमेन चुना गया, और अरूण मेहता, रामसागर सिन्ह परिहार, और भारत शाह महासचिव चुने गये और जेमिन देसाई कोषाध्यक्ष चुने गये और इसके अलावा सम्मेलन ने तीन संयुक्त सचिव भी चुने।

भाजपा हटाओ, देश बचाओ

बेटी बचाओ, नारा नहीं, बेटियों को भाजपाई धमकी है?

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले देश के नामचीन पहलवान धरने पर हैं। वे यौन उत्पीड़न के आरोपी भारतीय कुश्ती फेडरेशन के पिछले 12 सालों से अध्यक्ष रहे भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिह को सजा दिलाने के लिए धरने पर हैं। यह दूसरी बार है कि देश के नामचीन पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर हैं। इससे पहले वे जनवरी में इस मामले में खेल मंत्रालय द्वारा एक कमेटी बनाये जाने के बाद धरने से उठ गये थे। परंतु खेल मंत्रालय द्वारा उस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किये जाने और भाजपा सांसद को बचाये जाने के प्रयासों के खिलाफ वे फिर से आंदोलित हो उठे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जुमला रटने वाली सरकार का आलम यह है कि मोदी के राज में यौन उत्पीड़न की एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही लिखी जा सकी है और पोस्को का मामला दर्ज होने के बाद भी आज तक भाजपा बाहुबली बृज भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है।

विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के पहलवान मोदी सरकार द्वारा आरोपी को बचाने से खासे नाराज हैं। लगता है कि वे अबकी बार निर्णायक अंदाज में मैदान में उतरे हैं और आरोपी भाजपा सांसद को जेल भेजकर ही दम लेंगे। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट सहित देश के शीर्ष पहलवान विरोध प्रदर्शन के लिए फिर से जंतर मंतर पहुंचे और सरकार से डब्ल्यूएफआई (भारतीय कुश्ती महासंघ) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली निगरानी समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। जिसे सरकार सार्वजनिक नहीं कर रही है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के बीच पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

इन अन्तर्राष्ट्रीय पहलवानों की नाराजगी का पता विनेश फोगाट के सवाल से ही लग जाता है जब वे पूछती हैं कि सरकारी समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने में कितना समय लगने वाला है। पहले ही तीन महीने हो चुके हैं और हम अब भी उनकी बात सुनने का इंतजार कर रहे हैं। क्या रिपोर्ट तब आएगी जब शिकायत दर्ज कराने वाली लड़कियों की मौत हो जाएगी?

अब सवाल यह है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं का नारा देने वाली मोदी सरकार इस पूरे मामले पर इस तरह की अपराधिक असंवेदनशीलता क्यों दिखा रही है। मोदी का नारा बेटी बचाओ भी एक जुमला है अथवा यह देश की बेटियों के अभिभावकों के लिए एक धमकी है कि अपनी बेटियों को भाजपा नेताओं से बचाओ? क्योंकि यह एक अकेला ऐसा मामला नहीं जिसमें पार्टी विद द डिफरेंस भाजपा का यह चाल, चरित्र और चेहरा सामने आया है। जब से भाजपा सत्ता में आयी है, वह अक्सर अपने इस रंग को दिखाती रही है।

कुलदीप सेंगर केस

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले दबंग भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर जून 2017 में बलात्कार करने का आरोप लगा। परंतु कानून व्यवस्था पर हवाई बातें करने वाली प्रदेश सरकार की पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तक नहीं लिखी। एक साल तक जब पीड़ित लड़की की एफआईआर पुलिस ने नहीं लिखी तो बाद में लड़की के परिवार वालों ने कोर्ट का सहारा लिया। हालांकि उसके बाद विधायक पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाता रहा। वहीं लड़की का कहना था कि न्याय के लिए वह उन्नाव पुलिस के हर अधिकारी के पास गई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई।

इस मामले में भाजपा विधायक और प्रदेश मशीनरी ने बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी। विधायक और उनके साथी पुलिस में शिकायत नहीं करने का परिवार पर दबाव बनाते रहे हैं और इसी क्रम में विधायक के भाई ने तीन अप्रैल को उनके पिता से मारपीट भी की। जिसके कारण संदिग्ध अवस्था में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत हो गई।

इसी प्रकार का एक मामला स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का है। जिस केस को योगी ने सत्ता में आते ही अपने करीबी स्वामी से केस वापस ले लिये थे। सीएम योगी ने इसी क्रम में अपने खिलाफ भी कई केस वापस ले लिये थे।

इसी प्रकार के हाथरस बलात्कार और हत्या के मामले में भी यूपी सरकार ने अपने प्रदेश की तथाकथित सख्त कानून व्यवस्था का रंग दिखाते हुए आरोपियों को बचाने में जान झौंक दी थी। यहां तक कि पुलिस ने पीड़िता का दाह संस्कार भी बलपूर्वक रात के अंधेरे में करवा डाला था।

महेश राठी

जम्मू का कठुआ केस

जम्मू के कठुआ में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले ने देश को पूरी दुनिया को हिला दिया था। तो वहीं भाजपा नेताओं ने आरोपियों के पक्ष में तिरंगा रैली निकालकर दुनिया भर में देश और तिरंगे दोनों को शर्मसार कर डाला था। इस पूरे मामले में भाजपा के जम्मू कश्मीर सरकार के दो मंत्री सीधे तौर पर शामिल रहे थे। दोनों मंत्रियों पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू एकता मंच के सदस्यों को कठुआ रेप अभियुक्तों की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए उकसाया था। लाल सिंह जम्मू–कश्मीर की बीजेपी–पीडीपी गठबंधन सरकार में वन मंत्री थे, जबकि चंद्र प्रकाश गंगा उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे।

कठुआ में आठ वर्षीय बच्ची से रेप के बाद उपजे रोष के माहौल में हिंदू एकता मंच नाम के एक संगठन ने मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली थी। इसी हिंदू एकता मंच के एक कार्यक्रम में जम्मू–कश्मीर सरकार के ये दोनों मंत्री शामिल हुए थे। टीवी चैनलों पर दिखाया गया कि लोगों को संबोधित करते हुए इन भाजपा नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई की भी आलोचना की थी। इसे 'जंगल राज' कहते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि वे इस क्षेत्र के बेकसूरश लोगों को परेशान न करें। वन मंत्री चौधरी लाल सिंह ने सार्वजनिक तौर पर कठुआ रेप केस के आरोपियों के पक्ष में उतरे प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई आंदोलन करते हैं तो पूरी ताकत से करो, वरना घर बैठो। ये धारा 144 क्या है? एक लड़की मर गई और इतनी जांच हो रही है। यहां पहले भी कई महिलाओं की मौतें हो चुकी हैं। ऐसे ही एक वीडियो में चंद्रप्रकाश गंगा कहते हुए नजर आते हैं कि हम ये जंगल राज नहीं चलने देंगे। पुलिस अपनी मर्जी से लोगों को उठा रही है। ये किस तरह की जांच कर रहे हैं? यही भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा है कि वे ना केवल ऐसे मामलों में लिप्त पाये जाते हैं बल्कि बलात्कारियों को बचाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज लेकर रैली भी निकालते हैं।

हरियाणा का गीतिका शर्मा केस

कल ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला जिससे पूरे देश की जनता शर्मसार हुई थी। अंदाजा लगाईये कि इस मामले से पूरे हरियाणा की जनता कितनी शर्मसार हुई होगी? कि मीडिया के वह लोग जिन्होंने गीतिका शर्मा के केस में रिपोर्टिंग की होगी, उनकी आंखों में भी आंसू आ गये थे। एक ऐसा व्यक्ति गोपाल कांडा जिसने एक महिला का बलात्कार किया और जिसके चलते उस महिला ने खुदकुशी कर ली, पुलिस ने उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की, मजबूरन कोर्ट के द्वारा उस पर 376 का मुकदमा दायर करवाया गया और यही नहीं जब उस रेप पीड़िता की मां को न्याय नहीं मिला, तो 6 महीने बाद मजबूरी वश उस मां ने भी खुदकुशी कर ली। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली निंदनीय और घृणित घटना नहीं हो सकती। गोपाल कांडा हरियाणा में भाजपा सरकार का सहयोगी और सहभागी रहा है।

दरअसल, जब यह कांड उजागर हुआ तो उस समय गोपाल कांडा हुड्डा सरकार में मंत्री थाा और इस मामले के सुर्खियों में आने के बाद उसने इस्तीफा दे दिया था और कांडा को जेल भी जाना पड़ा था। उस समय भाजपा गोपाल कांडा के विरोध में और गीतिका को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर थी। परंतु 2019 में जब भाजपा ने हरियाणा में 40 सीटें जीती और सरकार बनाने के लिए उसने जोड़ तोड़ शुरू की तो यही गोपाल कांडा अब पवित्र होकर भाजपा की डुबती नाव का तारणहार बन गया था। जिसे सिरसा से भाजपा की सांसद सुनीता दुग्गल चार्टड विमान में लेकर दिल्ली पहुंच गयी थी।

जबलपुर भाजपा नेता

जबलपुर के भाजपा नेता पर 28 वर्षीय युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर रेप और पैसा ऐंठने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवती की शिकायत पर भोपाल पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ रेप सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में पीड़ित युवती ने जबलपुर भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के पूर्व जिला संयोजक शशिकान्त सोनी पर रेप का आरोप लगाया है।

पीड़िता का आरोप है कि जबलपुर नगर निगम कार्यालय में नौकरी का फॉर्म भरने के दौरान उसकी पहचान भाजपा नेता से हुई थी जिसके बाद भाजपा नेता ने भोपाल से उसे नौकरी दिलाने का वादा किया और दो लाख रूपए की मांग की। जिसके बाद भाजपा नेता पीड़िता को भोपाल लेकर आया और टीटीनगर इलाके में कार में रेप किया। पीड़िता का कहना है कि भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के पूर्व जिला संयोजक शाशिकान्त सोनी ने युवती को सरकारी नोकरी दिलवाने के झांसा दिया और उसे अपनी कार से भोपाल लेकर आया और दिनभर घूमता रहा। इसके बाद रात को टीटी नगर स्टेडियम के पीछे उसने कार में रेप किया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर वापस जबलपुर ले गया और हाईवे पर अकेला छोड़ दिया।

विजय जौली मामला

दिल्ली के पूर्व बीजेपी विधायक विजय जौली पर एक महिला के साथ रेप का सनसनीखेज आरोप लगा है। इस मामले में पीडिता की तहरीर पर गुरुग्राम में विजय जौली के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 328 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। वहीं, विजय जौली ने रेप के इस आरोप को मनगढंत बताते हुए अपने खिलाफ साजिश बताया है।

शहनवाज हुसैन

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने तक में पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और शहनवाज हुसैन को मामले में कोई राहत नहीं मिल पाई।

शेष पेज 4 पर...

बेटी बचाओ, नारा नहीं, बेटियों को भाजपाई धमकी...

पेज 3 से जारी...

असम का भाजपा नेता रेप केस में

असम कांग्रेस ने तिनसुखिया जिले में एक स्थानीय भाजपा नेता पर एक 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगाया था। विपक्षी दल ने राज्य महिला आयोग को एक शिकायत सौंपी और दावा किया कि आरोपी को इस तथ्य के बावजूद छोड़ दिया गया कि उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी क्योंकि वह सत्ताधारी पार्टी का नेता है। पीड़िता की मां ने भी आत्महत्या कर ली है। असम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मीरा बोरठाकुर ज्ञापन सौंपने के लिए राज्य महिला आयोग के कार्यालय गईं थीं। आरोप लगाया गया है कि तिनसुकिया के बोरदुबी इलाके में एक स्थानीय भाजपा बूथ समिति के अध्यक्ष समेंद्र रॉय उर्फ समुद्र रॉय ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया था। तिनसुकिया जिले के बोरदुबी इलाके में एक 13 वर्षीय नाबालिग के साथ एक भाजपा बूथ अध्यक्ष द्वारा बलात्कार की घटना सामने आई थी। हालांकि बोरदुबी पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करने सहित अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसका लाभ लेकर भाजपा के कई स्थानीय सदस्यों ने मुकदमा वापस लेने के लिए परिवार पर दबाव बनाया है। पीड़िता की मां ने परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ होने के बाद 14 अप्रैल को कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी।

बिलकिस बानो केस

2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहाई के सरकार के फैसले ने फिर से भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा यदि थाने के स्तर पर अपने लोगों को बचाने में नाकाम रहती है तो सजा में राहत देकर उनका बचाव कर लेती है। बेशक वे हत्यारे और बलात्कारी ही हों।

हत्यारे और बलात्कारियों के छूटने के कारण बिलकिस बानो और उनके पति ने मीडिया से कहा कि यह दुखद है। हमने सब कुछ गंवा दिया। इन लोगों की रिहाई से हमारा डर और बढ़ गया है।

3 मार्च 2002 को गुजरात दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में भीड़ ने बिलकिस बानो के परिवार पर हमला कर दिया था। 21 वर्षीय बिलकिस उस समय गर्भवती थी। उस समय बिलकिस के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया एवं उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई। अफसोसजनक तरीके से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही माफी नीति के तहत जसवंत नाई, गोविंद, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशरभाई वोहानिया, प्रदीप मोढ़डिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना को रिहा किया गया। 2008 में मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस सजा को जारी रखा था। सभी दोषी 15 साल से अधिक समय तक सजा काट चुके थे। इस आधार पर इनमें से एक अभियुक्त राधेश्याम शाह ने सजा में छूट के लिए अपील की थी।

शहडोल रेप केस

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक फार्म हाउस में 20 वर्षीय युवती के साथ कथित रूप से भाजपा के एक पदाधिकारी सहित चार लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने है। शहडोल जिले के भाजपा अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह ने कहा कि सामूहिक बलात्कार मामले में विजय त्रिपाठी का नाम आने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से जैतपुर मंडल अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया गया और पार्टी से उसकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी गई।

पुणे में भाजपा नेता पर केस

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता पर 32 वर्षीय एक महिला के साथ कथित रूप से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर एक कमरे में महिला के साथ बीजेपी नेता का एक वीडियो वायरल होने के बाद श्रीकांत देशमुख ने पार्टी के सोलापुर जिलाध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला का आरोप है कि देशमुख ने शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और पुणे, मुंबई तथा सोलापुर में कई बार उनका यौन शोषण किया। उन्होंने बताया कि यहां डेक्कन जिमखाना पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 377 (अप्राकृतिक अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसे आगे की जांच के लिए सोलापुर पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया था।

सेक्स रैकेट चलाने वाला भाजपा नेता

भारतीय जनता पार्टी की मेघालय इकाई के उपाध्यक्ष बर्नाड एन मराक को अपने फार्म हाऊस पर कथित रूप से वेश्यालय चलाने को लेकर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार किया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी थी। मेघालय पुलिस ने शनिवार को पश्चिम गारो पर्वतीय जिले में पूर्व उग्रवादी नेता मराक के फार्म हाऊस पर छापा मारा था जहां से उसने छह नाबालिगों को मुक्त कराया था एवं 73 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। तब से मराक फरार चल रहे थे।

विदेश में भी नहीं थम रही भाजपाईयों करतूतें

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया में एक अदालत ने पांच महिलाओं से बलात्कार का दोषी पाया है। मीडिया ने उसे 'ऑस्ट्रेलिया के सबसे जघन्य बलात्कारियों में से एक' लिखा है।

ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के पूर्व चीफ बालेश धनकड़ ने नौकरी का झांसा देकर कई महिलाओं को अपने अपार्टमेंट और होटल में बुलाकर नशे की दवा देकर उनका रेप किया और वीडियो बनाये। भारत के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से पढ़ाई करने वाला बालेश धनखड़ ऑस्ट्रेलिया में 'ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी' संगठन का अध्यक्ष था। नवंबर 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आए थे तो उनके स्वागत में सभी कार्यक्रम धनखड़ की देखरेख में ही हुए थे। वह दिल्ली में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में भी बतौर मेहमान शामिल हुआ था।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान इस मामले की इंचार्ज पुलिस अधिकारी सार्जेंट कटरीन गाईड ने कहा कि उन्हें संदेह है कि धनखड़ एक विक्षुब्ध फंतासी को जी रहा था। पुलिस ने धनखड़ के पास से 95 मिनट लंबा एक वीडियो बरामद किया था जिसमें बेहोश महिलाओं के साथ सेक्स किया जा रहा था।

अदालत में धनखड़ की पत्नी ने उसके समर्थन में बयान दिया. इस दौरान कई बार उनकी आंखें भर आई थीं।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस ऑफ न्यू साउथ वेल्स के प्रवक्ता डॉ. यदु सिंह कहते हैं कि बालेश धनखड़ ने जो किया था वह घोर गलत था। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। मुझे खुशी है कि न्यायालय ने उसे 5 महिलाओं के साथ यौन दुराचार के लिए अपराधी पाया है। इन जघन्य अपराधों के लिए उसे लंबे समय की जेल होनी चाहिए। बालेश की इन राक्षसी प्रवृत्ति के कार्यकलापों से भारतीय समुदाय की छवि धूमिल हुई है। बालेश सिडनी की कई भारतीय सामुदायिक संस्थाओं और बीजेपी से जुड़े ऑस्ट्रेलिया के संगठन का नेता था।

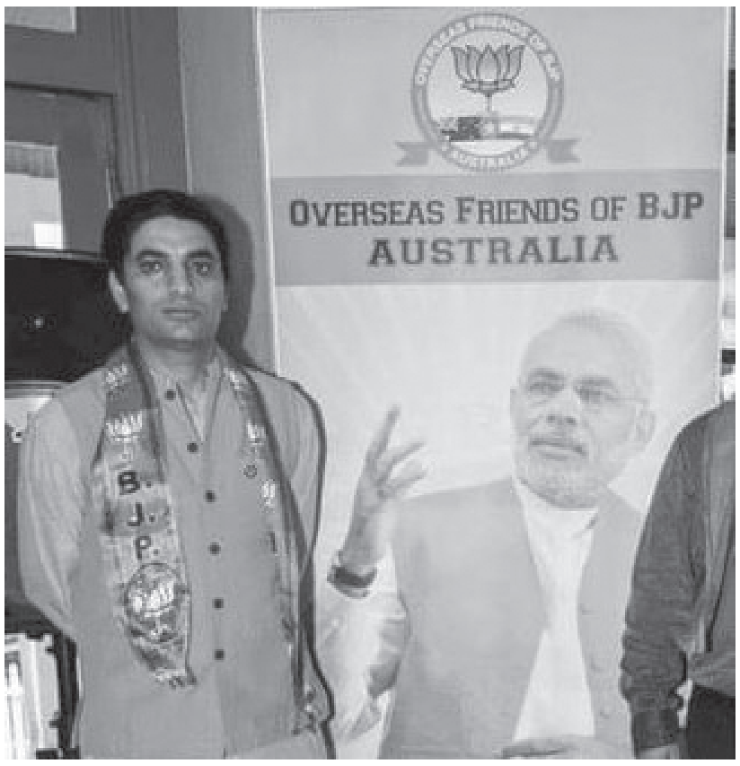

नहीं थम रहा है महिलाओं का शोषण

लंबे से समय में, जब महिलाओं से जुड़े अपराध का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है और इसके लिए कड़ा कानून बनाने की मांग उठ रही है, खुद कानून बनाने वाले ही महिला अपराध से जुड़े गंभीर मुकदमों का सामना कर रहे हैं। कुछ विधि निर्माता जन प्रतिनिधि नेता तो बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर मामले तक झेल रहे हैं।

इन मामलों में शील भंग करने के इरादे से किसी महिला पर हमला, अपहरण या शादी, बलात्कार, घरेलू हिंसा एवं मानव तस्करी के लिए मजबूर करने से संबंधित मामले शामिल हैं। चुनाव सुधार की दिशा में काम करने वाली संस्था एडीआर (एसोसिएशन ऑफ डेमाक्रैटिक रिफॉर्म्स) की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा के सबसे ज्यादा सांसद और विधायकों के खिलाफ इससे जुड़े केस लंबित हैं। वहीं, शिवसेना और टीएमसी दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। 12 भाजपा के सासंदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं, शिवसेना के 7 और टीएमसी के 6 विधायकों पर महिला अपराध से जुड़े मामले दर्ज हैं।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का जुमला आगे बढ़ाने वाले मोदी के नेतृत्व में देश में महिलाओं की दुर्दशा अकल्पनीय रूप से बदतर है। देश में हर साल 40 हजार, हर रोज 109 और हर घंटे 5 लड़कियों की अस्मत लूट ली जाती है। इस देश में जीडीपी गिरने की खबरें आती हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि रेप के मामलों में कमी आई हो। पिछले 10 साल में करीब 2.79 लाख रेप के मामले दर्ज किए गए, औसतन 40 हजार में से 10 हजार रेप के मामले नाबालिग बच्चियों के थे, हर साल 2000 ऐसे मामले होते हैं जिनमें पीड़िता का गैंगरेप किया गया, रेप के मामलों में सिर्फ 25 फीसदी बलात्कारियों को ही सजा मिल पाती है, रेप के 71 फीसदी मामले तो ऐसे हैं जिन्हें रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है। देश की लोकसभा और विधानसभा में बैठे 30 फीसदी नेताओं का आपराधिक रिकार्ड है, जिनम 51 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध किए जाने के मामले दर्ज हैं। मोदी का अपराधियों को जेल भेजने का दावा जितना झूठ था तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है कि बेटियों के अभिभावकों के लिए सीधी धमकी है कि हमारे नेताओं से बचाओ बेटी और बचा पाओगे बेटी तभी तो पढ़ा पाओगे बेटी।

विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन: अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग का हितरक्षक

सी. श्रीकुमार

विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 3 अक्टूबर 1945 को पेरिस में की गई थी। इस प्रकार यह यह सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठन है।

विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन एक ऐसा वर्ग–उन्मुखी ट्रेड यूनियन आदोलन है जो पूंजीवादी/साम्राज्यवादी बर्बरता के खिलाफ और इंसान द्वारा इंसान के शोषण से मुक्त समाज के लिए संघर्ष करता है। विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन के 133 देशों में 11 करोड़ 10 लाख सदस्य हैं। फेडरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सभी प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कन्वेंशनों के निर्माण एवं स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जिनमें कन्वेंशन 87 (संगठन बनाने की स्वतंत्रता) भी शामिल है।

अपने समूचे इतिहास के दौरान विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने नस्लवाद, रंगभेद और उपनिवेशवाद के खिलाफ और साथ ही अमरीका, इस्राइल, नाटो एवं उनके सहयोगी साम्राज्यवादी देशों की नीतियों के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। श्रम एवं ट्रेड यूनियन अधिकारों के संघर्षों में फेडरेशन अगले मोर्चे पर रहा है। विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन विचारधारा, धर्म, भाषा, लिंग, नृवंशीयता आदि का भेदभाव किये बगैर पूंजीवादी एवं साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ उनके संघर्षों में जनता को एकताबद्ध करने की दिशा में काम करता रहा है।

ट्रेड यूनियनों के इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गठन के लिए फरवरी 1945 में लंदन में एक कांफ्रेंस का आयोजन किया गया था जिसके घोषणा पत्र में रेखांकित किया गया था: ''युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए संगठित मजदूरों ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है तो भी वह इस बात को अन्य लोगों–भले ही उनके इरादे कितने भी अच्छे हों–पर ही शांति स्थापित करने के लिए एकमात्र जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता। यह एक अच्छे किस्म की शांति होगी, शाश्वत शांति होगी और ऐसी शांति होगी जिसमें स्वतंत्र लोगों, उनके हितों, उनकी आशाओं–आकांक्षाओं के लिए गंभीर संकल्प प्रतिबम्बित होगा।''

अपने स्थापना के दिनों से ही पिछले 78 वर्षों से अधिक समय से विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन चार बुनियादी संगठनात्मक सिद्धांतों के अनुसार काम कर रहा है। यह हैं एकताबद्ध करना, सार्वभौम, लोकतांत्रिक और वर्ग आधारित चरित्र। आज भी फेडरेशन इन चार सिद्धांतों के साथ काम कर रहा है।

आज विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन के सामने अनेकों चुनौतियां हैं। पूंजीवाद का संकट दुनिया भर में गहरा रहा है जिसके फलस्वरूप लोकतांत्रिक एवं ट्रेड यूनियन अधिकारों का सरासर उल्लंघन हो रहा है। मजदूर वर्ग की काम करने और जीने की परिस्थितियां बदतर होती जा रही हैं। सामाजिक असमानता बढ़ रही है। फलस्वरूप गरीबी और शोषण बढ़ रहा है। अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों की मदद के साथ पूंजीपति और कार्पोरेट तबका जिस तरह भी संभव हो इस संकट को मजदूर वर्ग पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वह संकट के तमाम दुष्परिणामों को मजदूर वर्ग, पेंशनयाफ्ता लोगों, बेरोजगार युवकों, महिलाओं, किसानों और स्वरोजगार में लगे सबसे गरीब लोगों के ऊपर डालने की दिन–रात कोशिश कर रहे हैं।

सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। मजदूर वर्ग इसका जबर्दस्त शिकार है। मजदूरी में कटौती करना, काम के घंटे बढ़ाना, रोजगार खत्म होना जैसी बातें आम हो गई हैं। इस कारण न केवल भारत में बल्कि इंग्लैंड, अमरीका, फ्रांस, ग्रीस, इटली, जर्मनी, लैटिन अमरीकी देशों, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि में भी मजदूर वर्ग संघर्ष के रास्ते पर है; रैलियां निकाल रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और हड़तालें कर रहा है। मजदूरों की प्रमुख मांगें हैं: रोजगार, रोजगार सुरक्षा, वाजिब मजदूरी, काम के कम घंटे, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा, महिला मजदूरों के अधिकार और कार्यस्थलों पर उत्पीड़न एवं हिंसा का खात्मा आदि। इन मांगों के लिए दुनिया भर में मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। इन संघर्षों में विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन से संबद्ध ट्रेड यूनियन लड़ाई के अगले मोर्चों पर हैं।

कोविड–19 महामारी के दौरान मजदूर वर्ग ने बहुत कुछ भुगता है। अब साम्राज्यवादी और पूंजीवादी ताकतें चाहती हैं कि अमरीका, नाटो और यूरोपियन यूनियन मिलकर यूक्रेन में रूस के खिलाफ जो साम्राज्यवादी युद्ध कर रहे हैं, मजदूर वर्ग उसका खर्च उठाये। जो लोग इस युद्ध में मुसीबत का सामना कर रहे हैं, विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन जिस तरह भी संभव हो सके उनकी मदद का समर्थन करता है। विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन चाहता है कि संप्रभु एवं स्वतंत्र देशों में विदेशी साम्राज्यवादी हितों को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने वाले आर्थिक युद्ध और प्रतिबंध खत्म किये जायें।

समाजवादी क्यूबा के खिलाफ अपराधपूर्ण नाकेबंदी जारी है। फलस्तीन की जनता के खिलाफ लगातार अपराध किये जा रहे हैं। इन बातों के खिलाफ विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन लगातार अपनी आवाज उठा रहा है और मांग कर रहा है कि इसे बंद किया जाये।

अंतर्राष्ट्रीयतावाद और एकजुटता विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन के शक्तिशाली हथियार हैं। विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन यह सुनिश्चित करने के लिए श्रम करता है कि कोई मजदूर यह महसूस न करे कि वह अकेला है।

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2023 (मई दिवस) के अवसर पर विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने उपरोक्त बातों को अपने मई दिवस घोषणा पत्र में दोहराया है और दुनिया भर में जो मजदूर अपनी मांगों एवं सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है और उन्हें अपना वर्ग अभिनंदन प्रेषित किया है।

विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन और उससे संबद्ध ट्रेड यूनियनें हरेक देश में, हरेक क्षेत्र में और हरेक उद्योग में मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए, उनके स्वयं के वर्ग हितों को हासिल करने के लिए और गरीबी, कंगाली, युद्ध को खत्म करने की आवश्यकता के लिए और एक ऐसा मानव केन्द्रित समाज बनाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगी जहां हर इंसान सम्मानपूर्वक जी सके, सम्मान पूर्वक काम कर सके, पूंजीवादी बर्बरता से समाज मुक्त रहे और इंसान द्वारा इंसान का शोषण न किया जा सके।

मई दिवस जिंदाबाद!

विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन जिंदाबाद!!

मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता जिंदाबाद!!!

राजेंद्र रघुवंशी स्मरण संगोष्ठी

आगरा: जन नाट्य केंद्र मदिया कटरा, आगरा पर नाट्य पितामह राजेन्द्र रघुवंशी के 104वें जन्म दिवस के अवसर पर आगरा इप्टा द्वारा एक स्मरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

यह स्मरण संगोष्ठी नाटक पितामह स्वर्गीय राजेंद्र रघुवंशी को समर्पित थी।

दिलीप रघुवंशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। सभी उपस्थित जन ने राजेंद्र रघुवंशी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता एम. पी. दीक्षित ने की।

डॉ. शशि तिवारी ने राजेंद्र रघुवंशी से संबंधित अपनी मधुर स्मृतियों को साझा किया। डॉक्टर ज्योत्सना रघुवंशी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। डॉक्टर ज्योत्सना रघुवंशी ने राजेंद्र रघुवंशी की बहुमुखी प्रतिभा का स्मरण किया।

दिलीप रघुवंशी ने राजेंद्र रघुवंशी जी के जन्म से लेकर और अंतिम सांस तक कला, साहित्य, पत्रकारिता, नाट्यकला, गीत, संगीत आदि में राजेंद्र रघुवंशी के उल्लेखनीय योगदान का स्मरण किया।

एम. पी. दीक्षित ने अपने राजेंद्र रघुवंशी के साथ संस्मरणों को साझा किया। नीरज मिश्रा ने भी अपने संस्मरण साझा किए।

इप्टा आगरा के कलाकारों ने राजेंद्र रघुवंशी रचित गीतों की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। सर्वप्रथम भगवान स्वरूप योगेन्द्र ने राजेंद्र रघुवंशी रचित गीत 'शहीदों तुमको मेरा सलाम' प्रस्तुत किया। जय कुमार ने कविता 'मैं भी कैसा पत्रकार हूँ' को प्रस्तुत किया। संगीत पक्ष परमानंद शर्मा ने संभाला और उनका साथ दिया भगवान स्वरूप योगेन्द्र, जय कुमार व सूर्यदेव ने।

इप्टा की आगरा इकाई के अध्यक्ष सुबोध गोयल ने भी अपने विचार रखे। राजीव शर्मा ने राजेंद्र रघुवंशी से अपने भावनात्मक लगाव को साझा किया व नाट्य पितामह पर लिखित रचना को प्रस्तुत किया।

उपस्थित हस्ताक्षरों में कुमकुम रघुवंशी, प्रियंका मिश्रा, मुदित जैटली, प्रताप सिंह कुशवाह, धर्मजीत, एस. के. खोसला आदि रहे।

संचालन की जिम्मेदारी दिलीप रघुवंशी ने संभाली व धन्यवाद शकील चौहान ने ज्ञापित किया।

डिलीवरी वर्कर को 'पार्टनर' कहना छलावा है

नए श्रमिकों की बढ़ती संख्या डिलिवरी वर्कर्स की है उनकी मांगों को उनके नियोक्ता अनदेखा कर रहे है, डिलिवरी वर्कर्स की सेवाएं आधुनिक वाणिज्य का अभिन्न अंग बन गई हैं। वर्तमान में, लगभग पांच लाख वर्कर्स पूरे भारत में इन नौकरियों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। फिर भी उनकी कार्य स्थितियों में कोई सुधार नहीं आया है, इसके कारण इन सभी को नौकरी पर रहते हुए अनावश्यक जोखिम और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

बड़े स्टार्ट–अप जो ऑन–डिमांड डिलीवरी के क्षेत्र में काम करते हैं, वे इस श्रम समूह का समुचित भुगतान किए बगैर उस पर निर्भर रहते हैं। डिलीवरी वर्कर्स के यूनियन में संगठित न होने और वर्कर्स के पास कोई अधिकार न होने के कारण इन डिलीवरी प्लेटफॉर्म की वर्कर्स के साथ लूटखसोट कानूनी चंगुल से बच जाती है।

बेंगलुरु स्थित सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ सोशल वर्क विभाग के छात्रों का दल एक अध्ययन के दौरान विभिन्न हाइपरलोकल होटल समूहों से और कई डिलीवरी वर्कर्स से मिला और उनके इन्टरव्यू लिए। उनका उद्देश्य इन इन्टरव्यू के माध्यम से डिलीवरी वर्कर्स की कार्य स्थितियों, भुगतान, सुरक्षा उपायों और शिकायत निवारण तंत्र को समझना था। मुख्यतः छात्रों ने स्टार्ट–अप्स द्वारा पोषित कार्य माहौल का अध्ययन किया, कि कैसे यह डिलीवरी श्रमिकों को प्रभावित करता है, और उन्होंने अपने अध्ययन में डिलीवरी वर्कर्स के उन मुद्दों को चिन्हित किया जिनके तत्काल समाधान की जरूरत है।

जमीनी स्तर पर छात्रों की डिलीवरी वर्कर्स की कार्य स्थितियों के बारे में दो महीने लंबी शोध से इकट्ठी की गई विस्तृत जानकारी के निष्कर्षों को यहाँ पेश किया जा रहा है।

इसके अलावा, डिलीवरी प्लेटफॉर्मो की कार्यप्रणाली और इन कार्यप्रणालियों से वे डिलीवरी 'पार्टनर' के साथ किस प्रकार के संबंध बनाते हैं उन्हें यहाँ रेखांकित किया गया है।

ये प्लेटफॉर्म डिलीवरी वर्कर्स को कर्मचारी के बतौर काम पर रखने की बजाय उनके साथ पार्टनरशिप को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वर्कर्स के साथ जुड़े आवश्यक सुरक्षा लाभों के प्रावधान को नाकाम किया जा सके। इन वर्कर्स को पेंशन फंड (पीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) जैसे बात तो दूर उन्हें यहाँ तक कि न्यूनतम वेतन जैसी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। इसके अलावा, काम में पार्टनर का दर्जा, डिलीवरी प्लेटफार्मो को कानूनों द्वारा निर्धारित अधिकतम कार्य घंटों से अधिक काम करने के लिए मजबूर करने से उनका शोषण करने की अनुमति देता है। वास्तव में, श्रमिकों को ओवरटाइम का भुगतान ओवरटाइम क्षतिपूर्ति प्रक्रिया से नहीं किया जाता बल्कि यह भी काम में पार्टनर की संरचना से किया जाता है। संगठित श्रम समूहों के साथ काम करने वाले नियोक्ता इन कानूनी संरक्षणों का सख्ती से पालन करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि संगठित श्रम समूह अक्सर यूनियनों में संगठित होते हैं।

किसी भी हाल में, डिलीवरी प्लेटफॉर्म 'गिग्स' और पार्ट–टाइम जैसे काम को बढ़ावा देते हैं, वे इस विचार को फैलाते हैं कि यह काम बहुत आरामदायक है और नियमित रोजगार या किसी और काम के साथ बिना किसी कठिनाई के किए जा सकता है। हालांकि, अध्ययन से पता चला है कि डिलीवरी वर्कर्स हर दिन दस से बारह घंटे से कम काम नहीं करते हैं। कई अन्य लोग चौदह घंटे से अधिक समय तक काम करने के लिए भी खुद को धकेलते हैं, जो कि इन वर्कर्स की आराम और अवकाश की जरूरत में रुकावट है। प्लेटफॉर्म जनित कामकाज जिस चीज का प्रचार करते हैं उस के खिलाफ जाते हैं, यहाँ वर्कर्स का बेहिसाब शोषण किया जाता है।

उचित मुआवजे की छवि की नकल करने के लिए, प्लेटफॉर्म हाई इनसेंटीव के वादों के साथ वर्कर्स को लुभाते हैं। हालांकि, वर्कर्स द्वारा साझा किए गए अनुभवों से पता चलता है कि जिन इनसेंटीव का वादा किया जाता है उन्हें कई कारणों का नाम लेकर काट दिया जाता है, कई ऐसे कारण होते हैं जिनके लिए वो जिम्मेदार नहीं होते। वर्कर्स ने इनसेंटीव को न देने वाले कई कारणों का उदाहरण दिया जैसे कि उनके डिलीवरी कोटा के पूरा होने से पहले रिवार्ड पीरियड का खत्म हो जाना और यहां तक कि इनसेंटीव देने से खुलेआम मना करना वर्कर्स की आम शिकायतें थीं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम वर्तमान में ब्लिंकिट डिलीवरी वर्कर्स के नेतृत्व में शहर भर में विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जिनके वेतन को अनुचित तरीके से कम कर दिया गया था। अन्य प्लेटफार्मो ने भी इस तरह की वेतन कटौती की है जो कि अतिरिक्त इनसेंटीव साधनों में अनुचित कटौती से भी अधिक है।

औसतन से कम इनसेंटीव देना जैसी कार्यप्रणालियाँ वर्कर्स अधिकारों पर खुली मार हैं, वहीं वर्कर्स अधिकारों

सूरज एम

की रक्षा करने वाली मौजूदा प्रणालियों को खत्म करना, कम दुर्भावनापूर्ण नहीं है। इसके अलावा गैर–भुगतान, मुआवजे में अचानक कटौती और दूसरी मुसीबतों में वर्कर्स को अपने भरण–पोषण का इंतजाम खुद करना होता है। वर्कर्स के सामने असंतोषजनक शिकायत तंत्र होता है जो जरूरी मदद नहीं करता। वे वर्कर्स को कई दिनों तक उनकी शिकायतों के किसी समाधान के इंतजार में छोड़ देते हैं। इस तरह के काम में, श्रमिकों के मुद्दों को तत्काल संबोधित करना आवश्यक है। वर्कर्स सड़क पर दुर्घटना के जोखिम का सामना करते हैं जो की उनके जीवन के लिए खतरा है। कुछ वर्कर्स ने नौकरी के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक वित्तीय सुरक्षा के इंतजार की शिकायत की है। वर्कर के ठीक होकर वापस काम में आने में मदद देने के लिए प्लेटफॉर्म इन वित्तीय सुरक्षा का वादा करते हैं। जो वादा किया जाता है वह पूरा नहीं किया जा रहा है, विशेष रूप से उन वादों को जिन्हें वर्कर्स के स्वास्थ्य और जीवन जोखिम स्थितियों में मदद करनी चाहिए।

यह कहना ठीक है कि उनके काम में पर्याप्त जोखिम हैं, उनके काम के साथ उनके नियोक्ताओं द्वारा की गई शर्तें उनके काम के जोखिम को बढ़ा रही हैं। ऑन लाइन प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को कम समय में भोजन या अन्य समान की डिलीवरी के वादे वर्कर को तेज गाड़ी चलाने के लिए मजबूर करते हैं, जो की सड़क पर खुद को और दूसरों को गंभीर जोखिम में डालते हैं। इसके कारण, डिलीवरी वर्कर्स को अक्सर यातायात पुलिस कर्मी आसानी से जुर्माना ऐंठने के स्त्रोत के रूप में निशाना बनाते हैं।

बहुत ज्यादा फोन लाइन पर रहने से डिलीवरी वर्कर्स जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है। डिलीवरी सर्विसेज अब तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं, जिसके कारण और अधिक व्यक्ति डिलीवरी वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। हालांकि, श्रमिकों के अधिकारों और मांगों का समर्थन करने वाली प्रासंगिक कानूनी व्यवस्थाएं मौजूद नहीं हैं। नतीजतन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) देश में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन कंफेडेरशन–डिलीवरी वर्कर्स को संगठित और एकजुट करने के लिए कदम उठा रहा है ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके और उनकी मांगों को पूरा किया जा सके।

एटक डिलीवरी वर्कर्स की जिन वर्तमान मांगों को सामने रख रही है, वह सर्वोपरि हैं ये मांगें डिलीवरी प्लेटफार्मो के अनुचित व्यवहारों और कार्यप्रणालियों को खत्म करेगी। डिलीवरी वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में शामिल करना, रोजगार सुरक्षा में वृद्धि, कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए हाइरिंग एजेंटों को हटाने और डिलीवरी वर्कर्स को 'आवश्यक सेवा' में उल्लेखित करना जैसी मांगें हैं। इसके अलावा, नियोक्ताओं को उनके वर्कर्स की मोटर साइकिल रखरखाव और मोबाइल रिचार्ज का खर्च वहन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियोक्ताओं को अपनी त्वरित डिलीवरी नीतियों को एक घंटे तक बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि डिलीवरी में तात्कालिकता को रोका जा सके और वर्कर्स की काम पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इन कमियों को दूर करके, डिलीवरी प्लेटफॉर्म उचित और स्थायी कामकाजी स्थिति उन वर्कर्स के लिए पैदा कर सकते हैं जो इन कारोबारों के मुनाफे के लिए मेहनत करते हैं। साफ है कि पीएफ, ईएसआई और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपाय जरूर होने चाहिए और बड़ी संख्या में यूनियन में संगठित होने से उनकी कठिनायों का समाधान होगा। किसी भी अन्य श्रम समूह की तरह, डिलीवरी वर्कर्स के शोषण के खिलाफ खड़े होना समय की मांग है। शोषण को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है।

भाकपा ओन्चिअम शहीद वेदी का अनावरण

सुरेश बाबू मुकेरी

ओन्चिअम शहादत की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति में 23 अप्रैल 2023 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवमंडल सदस्य डॉ. भालचंद्र कांगो ने शहीद वेदी का अनावरण किया। इस स्मारक का पुनर्निर्माण चैन्नाट्टुताड़ा वायल के नजदीक किया गया है। इस जगह 30 अप्रैल 1948 को पुलिस गोलीबारी में आठ भाकपा कामरेड मारे गए थे।

30अप्रैल 1948 में पुलिस ओन्चिअम गांव में पी.आर. नाम्बियार, एम. कुमार मास्टर, एम.के. केलु और अन्य नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए घुस आई थी। ये नेता भाकपा की कुरुमब्रांदु तालुक कमेटी को पार्टी कांग्रेस के निर्णय की रिपोर्ट करने आए थे। पुलिस को हजारों कामरेडों और ग्रामवासियों के मजबूत विरोध का सामना करना पड़ा जो कि इन नेताओं की गिरफ्तारी को रोकने के लिए इकट्ठे हुए थे।

पुलिस ने जनगण के खिलाफ गोलीबारी शुरू कर दी और आठ कामरेडों ने अपना जीवन खो दिया।

मनोदी कानन और कोल्लाचेरी कुमारन नाम के दो कामरेडों को पुलिस ने यंत्रणाएं दी और वे पुलिस हिरासत में मारे गए। यहां तक कि मृत्यु की कगार पर मनोदी कानन ने अपने खून से पार्टी निशान हसिया और हथौड़ा बनाया। यह ऐतिहासिक घटना केरल की जनता को भाकपा के नजदीक ले आई। पुलिस को ओन्चिअम जमींदारों के निर्देश पर भेजा गया था। भाकपा जमींदारों के खिलाफ लड़ रही थी और वहां उन्होंने किसानों को अन्याय और शोषण के खिलाफ संगठित किया था। जमींदारों ने अपने अस्तित्व के लिए भाकपा का दमन किया था। लेकिन इस घटना के बाद, मालाबार में जमींदार विरोधी और सामंत–विरोधी आंदोलन तेज हो गया था।

अपने संबोधन में, डॉ. कांगो ने भाजपा को हराने के लिए व्यापक गठजोड़ की जरूरत को दोहराया। उन्होंने कहा कि देश के मजदूर और किसानों को विपत्ति में धकेल दिया गया है और यहां तक कि भाजपा के शासन में संविधान को खतरा है। उन्होंने केरल के विकास मॉडल और कुडम्बश्री जैसे प्रयासों की सराहना की और केंद्र में केरल के मॉडल पर सरकार बनाने के लिए जोर दिया।

स्मृति उत्सव कार्यक्रम के दौरान पार्टी झंडारोहण केरल राज्य कार्यकारिणी सदस्य सत्यन मुकेरी ने किया। टी.के. राजन ने सभा की अध्यक्षता की। केरल राजस्व मंत्री के. राजन, एडवोकेट पी. बसंतम, टी.वी. बालन, के.के. बालन, पी. गवस, पी. के. नसर, पी. सुरेश बाबू और आर. सत्यन का कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया।

इन पिछले छह महीनों में क्रांतिकारी ओन्चिअम शहादत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोझीकोड में अलग–अलग जगहों पर अलग–अलग कार्यक्रम अयोजित किए गए थे। कोझीकोड शहर में एक इतिहास सेमिनार आयोजित किया गया था।, सेमिनार का उद्घाटन भाकपा राष्ट्रीय समिति सदस्य वाहिदा निजाम ने किया था। नादापुरम, कट्टीआडी और अयनचेरी में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

ऐतिहासिक चुनौतियों के दरमियान आज का मजदूर आन्दोलन

सत्यम सत्येन्द्र पाण्डेय

आज मजदूरों और मेहनतकशों की एकता और संघर्षों की जीत का अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार मई दिवस अर्थात अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस है। आज दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाने का दावा करने वाले इस बात को भुला देना चाहते हैं कि उनके इस प्रयास के सैंकड़ों पर पूर्व दुनिया के मेहनतकश अपने शोषण के खिलाफ और कुर्बानियां देते हुए अपनी विश्वव्यापी एकजुटता कायम कर रहे थे। पूंजीपतियों का यह भूमंडलीकरण सिर्फ पूंजी और पूंजीपतियों के पक्ष में था जबकि मजदूरों की अंतर्राष्ट्रीय एकता पूरी दुनिया की बेहतरी की बात करती है।

यदि हम भारत की बात करें तो उन्नीसवीं सदी के आखिरी दौर से मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई आरंभ हो गई थी। 1920 में देश के पहले केंद्रीय श्रमिक संगठन एटक की स्थापना प्रख्यात राष्ट्रीय नेता लाला लाजपतराय की अध्यक्षता में हुई और उसने न केवल मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी बल्कि श्रमिकों को आजादी की लड़ाई से भी जोड़ा। एटक की स्थापना के बाद मजदूरों के व्यापक संघर्षों में आई तीव्रता का परिणाम ही था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद को मजबूर होना पड़ा कि वह श्रमिक संघ, न्यूनतम मजदूरी और कारखाना अधिनियम आदि कानून बनाये।

आजादी के बाद जहाँ एक ओर एटक के नेतृत्व में मजदूर वर्ग ने मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक लामबंदी की और उभरते हुए पूंजीपति वर्ग द्वारा किये जा रहे शोषण के खिलाफ अपनी आवाज निरंतर बुलंद की तो दूसरी तरफ देश में व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना के लिए संघर्ष चलाया और राष्ट्र निर्माण में अपना अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। यह एटक जैसे क्रांतिकारी संगठन के ही संघर्षों का परिणाम था कि बैंक, बीमा, खदान आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया और देश में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की नीव डाली गई जिन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु आधुनिक भारत के तीर्थ कहते थे। लेकिन बीसवीं शताब्दी के आखिरी दशक में दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई जिनमे से एक सोवियत संघ का विखराव था और दूसरी घटना भूमंडीकरण था। इनका परिणाम दुनिया भर में आवारा पूंजीवाद के रूप में सामने आया और उदारीकरण के नाम पर सार्वजिक क्षेत्र को कमजोर करते हुए निजीकरण को बढ़ावा दिया जाने लगा। जाहिर है, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा और शासकीय नीतियों ने ही देश के सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर करना आरम्भ कर दिया और हर क्षेत्र में चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवाएं या उद्यम हों, धीरे–धीरे निजी हाथों में जाने लगे. इस दौर में उद्योगों की जगह सेवाओं का महत्त्व भी बढ़ा और वह भी निजी क्षेत्र के दायरे में। परिणाम यह हुआ कि मजदूरों के संगठन कमजोर होने लगे और उनके संघर्ष का संगठित स्वरुप कमजोर होता चला गया। आज जबकि देश में में फासीवादी विचार को मानने वाली एक सरकार सत्ताशीन है और वह खुलेआम देश की परिसंपत्तियों को नीलाम करने में लगी हुई है, तब देश का मजदूर वर्ग एक बार फिर व्यापक लामबंदी की राह पर है।

आज मजदूर आन्दोलन के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियाँ मौजूद हैं और उनके मद्देनजर कुछ कार्यभार हैं जो संक्षेप में विश्लेषित करने का प्रयास करता हूँ–

'असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का सवाल–' देश की कुल श्रम शक्ति का 90 फीसदी से अधिक हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से खेतिहर श्रमिक, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार और फुटपाथ विक्रेता आदि शामिल हैं। निजीकरण सहित अन्य शासकीय नीतियां इस संख्या को दिनरात बढ़ा रही हैं। ये वे श्रमिक हैं जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और कोई सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं है। इनके लिये न पुरानी पेंशन है और न नई। न प्रोविडेंट फण्ड का कोई प्रावधान है और न ग्रेच्युटी का। न सेवानिवृत्ति की कोई उम्र तय है और न उसका कोई आर्थिक लाभ। न कोई बीमा है और स्वास्थ्य की भी कोई सुविधा नही। जाहिर है, जब तक शरीर साथ देता है तब तक ही आमदनी है। आबादी के इतने बड़े हिस्से के इन अमानवीय स्थितियों में रहने के चलते देश की आर्थिक विकास की पूरी तस्वीर ही धूमिल हो जाती है। इसलिये श्रमिक संगठनों की आज यह पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इन मजदूरों के लिये समुचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा के लिये संघर्ष किया जाए।

'सार्वजनिक क्षेत्र पर खतरा' आज यह बहुत स्पष्ट है कि सरकार ने देश के सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और एक ऐसे क्रोनी पूंजीवाद को स्थापित करने में लगी हुई है जहाँ चुनिन्दा पूंजीपति ही लाभ कमाते हैं। इसके लिए नियम–कानूनों का मनमर्जी से बदला जा रहा है। राफेल सौदा इसका एक उत्कृष्ट उदहारण है जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को दरकिनार कर अम्बानी की कंपनी को निर्माण का काम दे दिया गया। हर माह किसी सार्वजनिक उद्यम को विनिवेश के नाम पर निजी हाथों में बेचा जा रहा है। जाहिर है, भाजपा को इसका लाभ भी मिल रहा है और हाल के वर्षों में कारपोरेट से उसे मिलने वाले चंदे में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इसका एक परिणाम यह हो रहा है कि देश में आर्थिक असमानता लगातार बढती जा रही है। देश के कुल 1 प्रतिशत पूंजीपतियों के पास देश की 50 प्रतिशत संपत्ति का सकेन्द्रण हो गया है। परिणामस्वरूप अधिकांश जनता गरीबी और भुखमरी की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए देश को बचाने के लिए आज की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़े हुआ जाये और संगठित संघर्ष किया जाये। एटक और अन्य वामपंथी श्रमिक संगठन यह काम सम्पूर्ण प्रतिबद्दता के साथ कर भी रहे हैं।

लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि मोदी सरकार या इनके पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की बढती अलोकप्रियता के कारण ही उसका निजीकरण करने में सफल हो सके हैं। आज कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पैसा हो और वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढाना चाहे या अपने परिजनों का इलाज सरकारी अस्पताल में कराना चाहे। सरकारी दफ्तरों और प्रतिष्ठानों में लालफीता शाही और भ्रष्टाचार सबसे गंदे स्वरुप में मौजूद हैं और जनता के साथ उनके कर्मचारियों का व्यवहार शत्रुओं की तरह होता है। जो व्यक्ति कर्मचारी यूनियन का सदस्य भी है, उसका व्यवहार भी एक आमतौर पर एक किसान या खेत मजदूर के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए जब सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं तो यह याद रखना चाहिए कि इसके साथ ही हमें इनके सार्वजनिक दायित्व सुनिश्चित करने की भी लड़ाई लड़नी होगी। देश की गरीब जनता तभी इनके साथ कड़ी होगी जब यह देश की गरीब जनता के साथ खड़े होंगे।

'श्रमिक हितैषी कानूनों का खात्मा–' श्रमिक संहिता के नाम पर मोदी सरकार ने श्रमिक हितैषी कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है। हालाँकि पूर्ववर्ती सरकारें भी यह करती रही हैं लेकिन यह सरकार जनता के व्यापक हिस्से का जिस तरह साम्प्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करके सफलता के साथ जन विरोधी कदम उठाती जा रही उससे चुनौती बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए आज सभी श्रमिक संगठनों को न केवल पूर्व के कानूनों को खत्म करने के खिलाफ व्यापक और दीर्घकालिक संघर्ष की तयारी करनी चाहिए बल्कि नए– नए उभर रहे क्षेत्रों जैसे आईटी सेक्टर में काम करने वाले युवाओं की सेवा शर्तों और सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून की मांगों को भी उठाना चाहिए ताकि आधार व्यापक हो सके।

'मेहनतकश वर्ग का बदलता हुआ स्वरुप और चरित्र–' आज हमारे देश में मेहनतकश वर्ग का स्वरुप बहुत बदल गया है। इसका कारण स्वयं पूंजीवाद के स्वरुप का बदल जाना ही है। आज का पूंजीवाद उद्योग प्रधान नहीं होकर सेवा या व्यवसाय की प्रमुखता वाला है, और वह वित्तीय पूंजी पर आधारित है। जिसके कारण पूंजीपतियों की संपत्ति में इजाफा इस कारण नहीं हो रहा कि फेक्टरी में बहुत उत्पादन हो रहा है बल्कि उनका मुनाफा शेयर मार्किट की गतिविधियों के चलते बढ़ रहा है। इसके अलावा तकनीकी के उन्नयन के चलते भी उत्पादन प्रक्रिया में श्रम की भूमिका पहले के मुकाबले कम हुई है। इसलिए आज बड़ी तादाद में असंगठित क्षेत्र के रोजगारों से आमआदमी अपनी आजीविका कमा रहे हैं जहाँ उन्हें किसी भी प्रकार के मालिक–मजदुर संबंधों का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ बहुत से उच्च तकनिकी शिक्षा प्राप्त युवा आईटी सेक्टर आदि नए व्यवसायों में काम कर रहे हैं परन्तु उनके काम के घंटे तय नहीं और कोई सेवा सुरक्षा प्राप्त नहीं है। वे दिन में 16 से 18 घंटे तक काल सेंटर में काम करते हैं और उन्हें कभी भी बिना नोटिस के नौकरी से हटा दिया जाता है। आज के मजदूर आन्दोलन के समक्ष यह बहुत बड़ी चुनौती है कि इन लोगों को कैसे संगठित कर शोषण के प्रतिकार के लिए तैयार किया जाये? मेरी राय में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और नए तरह के रोजगारों में संलग्न युवाओं को साथ लाये बिना आज एक सफल और प्रासंगिक मजदूर आन्दोलन की कल्पना नहीं की जा सकती है।

'जाति, वर्ग और लिंग का सवाल–' देश के वामपंथी श्रमिक आन्दोलन के साथ एक बड़ी समस्या रही है कि सिद्धांत के आधार पर तो उच्च नैतिक पक्ष का दावा किया जाता रहा है और व्यव्हार में बहुत ही सतही जुगाड़बाजी चलती रही है। जाति आधारित वंचना और अत्याचार के सवाल को हमारे मजदुर संगठनों में केन्द्रीय महत्त्व प्राप्त नहीं हुआ और यह कहा जाता रहा कि जैसे– जैसे पूंजीवाद सामंतवादी ढंाचे को अपदस्थ करता जायेगा, उसी अनुपात में जातिगत भेदभाव खत्म होता जायेगा और लोग अपनी वर्गीय पहचान को प्रधानता देने लगेंगे। चूँकि यह विश्लेषण वर्ग की सीमित समझ के कारण ही किया जा रहा था, इसलिए जाहिर है कि ऐसा कभी नहीं हुआ बल्कि जातिगत भेदभाव नए–नए स्वरूपों में प्रकट होता गया। हमारे देश में जातिगत विभाजन भी वर्गीय विभाजन का ही एक अलग तरह का स्वरुप है इसलिए जातिगत भेदभाव, शोषण और अत्याचारों के खिलाफ हमारा संघर्ष उतनी ही ताकत और ईमानदारी के साथ होना चाहिए था जोकि नहीं हो पाया। लगभग ऐसी ही बात हम लैंगिक भेदभाव के बारे में भी कह सकते हैं। सबकी मुक्ति एक साथ ही होगी के सूत्र वाक्य के साथ हम लोग भ्रामक नतीजे निकालते रहे और दिन ब दिन महिलाओं का शोषण और लैंगिक अत्याचार बढ़ते गए। स्वयं मजदूर संगठनों के अन्दर बड़ी संख्या में लोग जाति और लिंग के भेदभाव करते हुए भी नेता बने रहते हैं क्योंकि उनकी सांगठनिक क्षमताएं अन्यों से बेहतर हैं। इक्कीसवीं सदी का मजदूर आन्दोलन इन समस्याओं से मुंह छिपाकर नहीं किया जा सकता। इसलिए यह हमारी ऐतिहासिक जिम्मेवारी है कि हम मनुवाद– ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता के खिलाफ एक लम्बी और जुझारू लड़ाई का शंखनाद करें।

'सबको शिक्षा– सबको काम–' इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वाधीनता के बाद भारत में शिक्षा का जितना विस्तार हुआ उतना इतिहास के किसी भी दौर में कभी भी नहीं हुआ था और यही कारण है कि सदियों से वंचित रहे समुदायों के लोग भी शिक्षित होकर नौकरियों में आये और काफी हद तक उनका जीवन परिवर्तित हुआ। परन्तु आज शिक्षा के बड़े पैमाने पर निजीकरण के चलते एक बार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर चुनिन्दा लोगों का ही अधिकार है और अधिकांश आबादी के बच्चे घटिया सरकारी स्कूलों में पढने के लिए अभिशप्त हैं। इसका सीधा असर रोजगार पर भी पड़ता है और जो लोग पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं वे रोजगार से भी वंचित रहते हैं और जीवन यापन के लिए रोजगार गारंटी टाइप काम करने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए आज श्रमिक संगठनों द्वारा यह मांग उठाने का समय आ गया है कि देश में सभी के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जाये जहाँ अमीर और गरीब सबके बच्चे एक साथ बैठकर निशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। जाहिर है, ऐसा तभी संभव हो सकता है जब शिक्षा व्यवस्था का पूर्णरूपेण राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार की मांग को भी जन आन्दोलन का मुद्दा बनाये जाने की जरूरत है। ये वे

शेष पेज 15 पर...

कुछ सामयिक मुद्दे और घटनाक्रम

आर.एस. यादव

चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष?

3 मई को कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के लोगों से अपील की और कहा कि वे जब 10 मई को मतदान केंद्र पर जाएं और मतदान करें तो ''जय बजरंग बली'' बोल कर बटन दबाएं। खुलेआम इस प्रकार एक धार्मिक नारा देकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए कहना सरासर गलत है। पर क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है और इस संबंध में कार्रवाई करेगा?

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 11 पायदान नीचे खिसका भारत

पेरिस स्थित वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) दुनिया भर के देशों में प्रेस की स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। पिछले वर्ष आरएसएफ ने प्रेस की स्वतंत्रता के विषय में 180 देशों के सर्वेक्षण में भारत को 150वां स्थान दिया था। 3 मई 2023 (विश्व–स्वतंत्रता दिवस) को प्रकाशित उसकी रिपोर्ट में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 11 पायदान नीचे खिसक कर 161वें स्थान पर आ गया है। इसका अर्थ है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता में कमी आ रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन देशों–ताजिकिस्तान (जो एक पायदान गिरकर 153वें स्थान पर आ गया है), भारत (जो 11पायदान गिरकर 161वें स्थान पर आ गया है) और तुर्किये (जो 16 पायदान गिरकर 165वें स्थान पर आ गया है) में स्थिति ''समस्याग्रस्त'' से ''बहुत खराब'' हो गई है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करीबी धन्ना सेठों द्वारा मीडिया के हस्तातंरण ने बहुलवाद को ध्वस्त कर दिया है।

यह उल्लेख एनडीटीवी के अधिग्रहण के संबंध में है जिसका स्वामित्व अब अडानी कारपोरेट घराने के पास आ गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत की स्थिति पाकिस्तान से भी खराब है। पिछले वर्ष के दौरान भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 11 पायदान नीचे खिसक कर 161वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि पाकिस्तान पिछले वर्ष के 157वें स्थान से 7 पायदान ऊपर उठ कर 150वें स्थान पर आ गया।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार, श्रीलंका में भी प्रेस भारत के मुकाबले अधिक स्वतंत्र है। वर्ष 2023 के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में श्रीलंका पिछले वर्ष के 146वें स्थान से 11पायदान ऊपर उठकर 135वें स्थान पर आ गया है।

मोदी राज में प्रेस की स्वतंत्रता का जो हाल है, तालिबान द्वारा शासित अफगानिस्तान में भी उतना बुरा हाल नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में अफगानिस्तान 152वें स्थान पर है, जिसका अर्थ है कि अफगानिस्तान में प्रेस भारत से अधिक स्वतंत्र है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के इस क्षरण के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार न ठहराया जाए तो फिर किसे ठहराया जाए?

आरएसएफ के अनुसार, प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है: ''राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, एवं सामाजिक हस्तक्षेप के बिना और उनकी शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा को खतरे के बिना जनहित में खबरों को चुनने, पेश करने और प्रचारित–प्रसारित करने में व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर पत्रकारों का अधिकार और क्षमता।

इंडियन वीमैन्स प्रेस, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और प्रेस एसोसिएशन ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के क्षरण के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त बयान जारी किया है।

भ्रष्टाचार के प्रति ''जीरो टॉलरेंस'' का प्रधानमंत्री का दावा सरासर मिथ्या

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने जो अनेक लंबे–चौड़े वादे किए थे उनमें यह वादा भी था कि वह भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और भ्रष्टाचार के प्रति उनकी नीति ''जीरो टॉलरेंस'' की रहेगी। परंतु उनके सत्ता में आने के बाद खत्म होना तो दूर रहा, भ्रष्टाचार में लगातार वृद्धि होती रही। ''जीरो टॉलरेंस'' का दावा करने वाले प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार के आरोपी लोगों के साथ निकटता और घनिष्ठता बार–बार देखने में आती है। इसका एक बड़ा उदाहरण भाजपा के कर्नाटक के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था। उनके और उनके परिवार के कुछ अन्य लोगों पर भ्रष्टाचार के साफ–साफ मामले थे परंतु आज तक उन मामलों में गंभीरता से कोई कार्रवाई नहीं हुई। येदियुरप्पा प्रधानमंत्री के करीबी लोगों में से हैं।

भ्रष्टाचारी तत्वों के साथ प्रधानमंत्री की निकटता का एक नवीनतम उदाहरण हैं भाजपा के ही एक अन्य नेता ईश्वरप्पा।

हाल ही में ईश्वरप्पा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह फोन पर प्रधानमंत्री से बात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में प्रधानमंत्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है, ''आपने पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। मैं आपसे बहुत खुश हूं''। ईश्वरप्पा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे ''पार्टी का एक अनुशासित सिपाही और अन्य के लिए एक ''रोल मॉडल (आदर्श पुरूष)'' होने का नाम दिया''।

बेलगावी में सार्वजनिक कार्यों पर 40 प्रतिशत कमीशन लेने का ईश्वरप्पा पर आरोप लगाते हुए एक ठेकेदार संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर ली थी। संतोष पाटिल भाजपा का कार्यकर्ता था। उसे शायद उम्मीद थी कि भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते उससे 40 प्रतिशत कमीशन नहीं लिया जाएगा। संतोष पाटिल की आत्महत्या के बाद ईश्वरप्पा को अप्रैल 2022 में ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के पद से हटना पड़ा। कर्नाटक की ठेकेदार ऐसोसिएशन ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य में हरेक काम पर 40 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है।

भ्रष्टाचार में लिप्त रहे ईश्वरप्पा से प्रधानमंत्री ''बहुत खुश'' हैं और ईश्वरप्पा को एक ''रोल मॉडल'' का नाम देते हैं। क्या यही है भ्रष्टाचार के प्रति ''जीरो टॉलरेंस''?

कुछ सप्ताह पहले कर्नाटक में लोकायुक्त अधिकारियों ने भाजपा के विधायक मदल विरूपक्षप्पा के बेटे प्रशांत कुमार को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था और उसके घर से 6 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी भी बरामद की गई थी। प्रशांत कुमार कथित रूप से अपने पिता की ओर से रिश्वत की पहली किश्त ले रहे थे। क्या यह कर्नाटक में भाजपा राज में ''40 प्रतिशत कमीशन'' का उदाहरण नहीं है?

3 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की भाजपा नीत पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार में मुख्य सचिव रहे अमन कुमार सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार एक कैंसर है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि मामला दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का ''दुरूपयोग'' था और आरोप प्रथम दृष्टतया संभावनाओं पर आधारित थे।

अमन कुमार सिंह के तार कहां–कहां जुड़े थे इसे इस बात से समझा जा सकता है कि बाद में नवंबर 2022 में वह अडानी कारपोरेट समूह के ''कारपोरेट कस्टोडियन एंड कारपोरेट अफेयर्स'' के प्रमुख बनाए गए। बाद में जब अडानी समूह ने समाचार चैनल एनडीटीवी को खरीदा तो उन्हें चैनल के बोर्ड के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया। अडानी समूह पर किसका वरदहस्त है यह हिन्डनबर्ग रिपोर्ट के संबंध में हुई चर्चाओं में साफ हो चुका है।

क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं कि उन्हीं की पार्टी के नेता किस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? भाजपा की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को दसवीं कक्षा बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में 5 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया गया। बंडी संजय कुमार भाजपा के संसद सदस्य भी हैं। वह प्रश्नपत्र लीक मामले के मुख्य मुल्जिम हैं।

भले ही कितना भी प्रचार किया जाता रहे कि मोदी के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार कम हो गया है, हर कोई जानता है कि भ्रष्टाचार न केवल बदस्तूर जारी है बल्कि पहले से अधिक है। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि भ्रष्टाचार एक कैंसर है, उसी दिन कर्नाटक में भाजपा विधायक के बेटे को अपने विधायक पिता की ओर से 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए अपने पिता के कार्यालय में ही रंगे हाथों पकड़ा गया।

''हमारे देश में अब यह सर्वस्वीकृत तथ्य है कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो सकता। विकास परियोजनाओं में ठेकेदारी हासिल करनी हो, सरकारी नौकरी पानी हो, यहां तक कि तहसील–तालुका से अपनी जमीन–जायदाद के कागजात हासिल करने हों, तो बिना रिश्वत के काम चल नहीं सकता। बहुत सारे सरकारी विभागों में तो अलग–अलग काम के लिए बाकायदा दरें निर्धारित हैं। हर ठेके में ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों–मंत्रियों आदि के कमीशन तय होते हैं। विचित्र बात तो यह भी है कि बहुत सारी जगहों पर किसी अधिकारी से मिलाने तक के लिए चपरासी पैसे मांग लेता है। इस तरह सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार खुल्लम–खुल्ला चलता है। यह कोई छिपी बात नहीं है। एक सामान्य आदमी भी किसी मामूली सरकारी कर्मचारी के ठाठ–बाट से अंदाजा लगा सकता है कि उसकी ''ऊपरी'' कमाई कितनी होती होगी। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने बहुत सारे कामों में पारदर्शिता लाने के मकसद से खिड़कियों पर कतार लगाने और अधिकारियों के चक्कर काटने की परंपरा खत्म करके इंटरनेट के जरिए काम कराने की व्यवस्था कर दी है। पर हकीकत यही है कि इसके बावजूद भ्रष्टाचार का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।

''भ्रष्टाचार की जड़ें सबको पता हैं। हर मंत्री और अधिकारी उन्हें पहचानता है, मगर दिक्कत यह है कि भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प सिर्फ नारों तक सिमट कर रह गया है। उसके लिए कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई देती। जब खुद मंत्री और उनके सचिव इस खेल में शामिल पाए जाते हैं, तो भ्रष्टाचार को मिटाने की उम्मीद भला किससे की जाए।........भ्रष्टाचार की जड़ों पर तब तक प्रहार संभव नहीं है,जब तक कि राजनीतिक नेतृत्व इसे लेकर खुद गंभीर न हो।'' (जनसत्ता, 6 मार्च, 2023)

प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भाजपा का भ्रष्टाचार के प्रति क्या रवैया है उसे एक अन्य उदाहरण से भी समझा जा सकता है। कर्नाटक में तुमकुरू जिले की मधुगिरि सीट से भाजपा ने विधान सभा चुनाव के लिए (जिसके लिए 10 मई को मतदान होना है) जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है उसका नाम है एल.सी. नागराज। वह 4,000 करोड़ रु. के आईएमए घोटाले का मुल्जिम है। उसने धोखाधड़ी के तरीके अपनाकर 41,000 लोगों के साथ ठगी की है। वह एक पूर्व नौकरशाह है। इस घोटाले की जांच सीबीआई ने की थी और नागराज को मुल्जिम बनाकर चार्जशीट दायर की थी। मुकदमा चल रहा है।

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के भाजपा के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में स्वयं प्रधानमंत्री भी शामिल थे।

चार हजार करोड़ रु. के घोटाले के मुल्जिम को भाजपा का उम्मीदवार बनाया जाना भ्रष्टाचार के संबंध में ''जीरो टॉलरेंस'' के प्रधानमंत्री के दावे की असलियत को सामने लाता है।

भाजपा नेता रहे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि

प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने गोवा में भ्रष्टाचार के संबंध में प्रधानमंत्री को बताया तो तुरंत ही मुझे गोवा के राज्यपाल के पद से हटा दिया गया।

सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जब वह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो अक्टूबर 2021 में आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उन्हें अंबानी से संबंधित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रु. की रिश्वत की पेशकश की थी। जब उनसे उस पदाधिकारी का नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया कि राम माधव ने, जो उस समय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव थे, यह रिश्वत देने की पेशकश की थी।

''परिवारवाद'' के संबंध में भाजपा के दावे

राजनीति में परिवारवाद कोई अच्छी बात नहीं है। परंतु अधिकांश राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद से ग्रस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य नेता अकसर अन्य पार्टियों पर ''परिवारवादी'' होने का आरोप लगाते रहे हैं। कर्नाटक के हाल के विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान भी उन्होंने अन्य पार्टियों पर इस तरह के आरोप लगाए। ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि भाजपा परिवारवाद के रोग से मुक्त है। परंतु वास्तविकता इसके सर्वथा विपरीत है।

कर्नाटक विधान सभा चुनाव (जिसके लिए 10 मई को मतदान होगा) में भाजपा ने 25 से अधिक ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जिनकी एकमात्र लियाकत इसके सिवा कुछ नहीं कि उनके माता या पिता भाजपा या अन्य किसी पार्टी के नेता रहे हैं। उदाहरणार्थः

– पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता येदियुरप्पा का बेटा विजयेन्द्र;

– पूर्व मंत्री आनन्द सिंह का बेटा सिद्धार्थ सिंह;

– पूर्व मंत्री रामचन्द्र गौडा का बेटा सप्तगिरि गौडा;

– पूर्व विधायक दम्पत्ति एच. नागप्पा और परिमल नागप्पा का बेटा प्रीतम;

– पूर्व एमएलसी मलिंगे गौडा का बेटा गौतम गौडा;

– पूर्व विधायक वाई. सम्पांगी की बेटी अश्विनी;

– पूर्व विधायक आनन्द ममानी की पत्नी रत्ना ममानी;

– ट्रांसपोर्ट मंत्री बी. श्रीमालू का भतीजा सुरेश बाबू;

– पूर्व मंत्री उमेश कट्टी का बेटा निखिल कट्टी;

– पूर्व मंत्री उमेश कट्टी का भाई रमेश कट्टी; आदि।

यह पहली बार नहीं कि भाजपा ने अपने नेताओं के भाई–भतीजों, बेटे–बेटियों और रिश्तेदारों को अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का एक बेटा पहले ही संसद सदस्य है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई के पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं यद्यपि वह भाजपा में नहीं थे; वह जनता दल के नेता थे।

मोदी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश गोयल के पुत्र हैं।

मोदी सरकार में मानव संसाधन मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे देवेन्द्र प्रधान के पुत्र हैं।

मोदी सरकार में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धूमल के पुत्र हैं।

मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू के पिता अरूणाचल विधान सभा के प्रो टैम स्पीकर रहे हैं।

मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया के बेटे और भाजपा की बड़ी नेता रही विजयराजे सिंधिया के पौत्र हैं।

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री जतिन प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितेन्द्र प्रसाद के पुत्र हैं।

हजारीबाग से भाजपा के सांसद और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे जयंत सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के पुत्र हैं।

गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से भाजपा विधायक पंकज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं।

भाजपा संसद सदस्य प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता साहिब सिंह के पुत्र हैं।

महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस (जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं) विधान परिषद सदस्य रहे गंगाधरपंत फडणवीस के पुत्र और राज्य मंत्री शोभा फडणवीस के भतीजे हैं।

भाजपा संसद सदस्य विवेक ठाकुर अटलबिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता सी.पी. ठाकुर के पुत्र हैं।

भाजपा सांसद नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के पुत्र हैं।

भाजपा संसद सदस्य दुष्यंत सिंह राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसंधुरा राजे सिंधिया के पुत्र हैं।

उत्तर प्रदेश में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुत्री हैं।

भाजपा संसद सदस्य सनी देओल भाजपा के पूर्व संसद सदस्य धर्मेंद्र कुमार के पुत्र हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे कल्याण सिंह के पुत्र राजबीर सिंह और पौत्र संदीप सिंह भी भाजपा राजनीति के कारोबार में हैं।

भाजपा के संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों में ऐसे लोगों की फहरिस्त काफी लंबी हैं जो केवल परिवारवाद के ही कारण राजनीति का कारोबार कर रहे हैं। फिर भी प्रधानमंत्री समेत भाजपा के किसी भी नेता को यह झूठा दावा करने में कोई झिझक नहीं होती कि भाजपा मे परिवारवाद नहीं है।

डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत भी पाठ्य पुस्तकों से बाहर

जनवरी 2018 में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय में तत्कालीन राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह ने कहा था कि डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत ''वैज्ञानिक तौर पर'' गलत है, इसे स्कूल–कॉलेज की पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया जाना चाहिए। जुलाई 2019 में उन्होंने इसी बात को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने या उनके पुरखों ने किसी बंदर को मानव में बदलते नहीं देखा है। उन्होंने दावा किया कि मानव ऋषियों के वंशज हैं, बंदर से विकसित होकर मानव नहीं बना। उनके कथन का भाजपा महासचिव राम माधव ने भी समर्थन किया।

जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, बड़े–बड़े लोगों द्वारा इस तरह के अवैज्ञानिक विचार प्रकट करने का मानो एक सिलसिला ही शुरू हो गया है। होता भी क्यों न जबकि स्वयं प्रधानंत्री को वैज्ञानिकों के एक सम्मेलन में यह कहते हुए कोई झिझक नहीं हुई कि प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी हुआ करती थी और गणेश के सिर पर हाथी के सिर के प्रतिरोपण को उन्होंने उसके एक उदाहरण के तौर पर बताया। आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति नागेश्वर राव गोल्लापल्ली ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस में 2019 में कहा कि ''दशावतार का सिद्धांत'' विकास की डार्विन के सिद्धांत से बेहतर व्याख्या करता है।

उल्लेखनीय है कि भारत का संविधान इस बात पर जोर देता है कि देश के नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। परंतु मोदी सरकार के दौरान इसका उलटा किया जा रहा है। लोगों के सामने ऐसे तर्क रखे जा रहे हैं जो पूरी तरह से अवैज्ञानिक हैं। यहां तक कि अंधविश्वास और पाखंडों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

हाल के दिनों में पाठ्य पुस्तकों में ऐसे अनेक बदलाव किए गए हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। बदलावों के उस सिलसिले में डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को भी पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया गया है। 2021–22 के एकेडेमिक वर्ष में कक्षा 9 एवं 10 के छात्रों के पाठ्यक्रम से डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को हटा दिया गया था। अब एनसीईआरटी ने दसवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में क्रम–विकास (इवोल्यूशन) के संबंध में पूरे के पूरे हिस्से को पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है।

डार्विन का विकास का सिद्धांत बताता है कि किस तरह मानव जीवन (और दुनिया में जीवन की तमाम अन्य किस्मों) का प्रारंभ हुआ; किस तरह क्रम–विकास (इवोल्यूशन) की लाखों–करोड़ों वर्ष चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया से जीवन पैदा हुआ और किस तरह हर किस्म के जीव–जन्तु विकसित हुए और किस तरह विकास के इस क्रम में मानव पैदा हुआ। डार्विन से पहले जीवन के विकास के संबंध में अलग–अलग स्थानों पर अलग–अलग आस्थाओं–धर्मो आदि द्वारा मानव जीवन की उत्पत्ति के संबंध में प्रस्तुत विभिन्न अवधारणाओं पर लोग विश्वास करते थे। इन अवधारणाओं में जो सबसे अधिक प्रचलित अवधारणाएं रही हैं उनमें एक अलौकिक शक्ति द्वारा मानव जीवन की उत्पत्ति की अवधारणा मुख्य है। इस अलौकिक शक्ति को प्रायः ''भगवान'' का नाम दिया जाता है। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने ''अलौकिक शक्ति'' की अवधारणा को खारिज कर जीवन की उत्पत्ति और एक लंबी अवधि में क्रम–विकास के जरिये मानव समेत विभिन्न जीव–जन्तुओं की उत्पत्ति के संबंध में एक वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत की। आज का जीव–विज्ञान और चिकित्सा–शास्त्र इसी वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है।

जीवन और जीवों की उत्पत्ति की इस वैज्ञानिक समझ को पाठ्य–पुस्तकों से हटाकर मोदी सरकार आखिर छात्रों को पढ़ाना क्या चाहती है? छात्र यदि डार्विन के विकास के सिद्धांत को नहीं पढ़ेंगे तो उसका परिणाम इसके सिवा क्या निकलेगा कि वे जीवन और जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अवैज्ञानिक एवं काल्पनिक बातों और अंधविश्वासों को ही सच समझते रहेंगे?

मनरेगा में घात

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एक ऐसी योजना है जो गांवों के गरीब बेरोजगारों के लिए एक आखिरी आसरे के समान है। इस योजना के प्रावधान के अनुसार गांव का जो भी बेरोजगार व्यक्ति रोजगार मांगे, उसे रोजगार देना आवश्यक है। इस योजना में एक परिवार को वर्ष भर में 100 दिन रोजगार मिलने की गारंटी है। यह योजना मांग आधारित है, बजट आधारित नहीं। जितने भी लोग काम मांगे, कानूनी रूप से बाध्यकारी है कि उन्हें काम दिया जाए। यह कहकर काम देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके लिए बजट कम है या खत्म हो गया है।

मोदी सरकार योजना में घात कर रही है। मोदी सरकार ने योजना के अंतर्गत काम करने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के जरिये हाजिरी और आधार–आधारित भुगतान सिस्टम को आवश्यक बना दिया है। साथ ही योजना के लिए आवंटित फंड में कमी कर रही है। वित्त वर्ष 2023–24 में मनरेगा के लिए जो आवंटन किया गया वह वित्त वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमानों से 29,400 करोड़ रुपए कम है।

इसका नतीजा यह निकल रहा है कि इस योजना के तहत काम करने वाले परिवारों की संख्या कम हो गई है और जिन परिवारों को काम मिल रहा है, उन्हें योजना के अनुसार पूरे 100 दिन काम नहीं मिलता।

मनरेगा पोर्टल डाटा के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान मनरेगा के तहत 6.19 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला जबकि वित्त वर्ष 2020–21 में 7.55 करोड़ और वित्त वर्ष 2021–22 में 7.25 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला था।

इसी प्रकार प्रति परिवार को वर्ष भर में औसतन जितने दिन रोजगार मिला, वह भी कम हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2022–23 में प्रति परिवार को वर्ष भर में औसतन 47.84 दिन रोजगार मिला जबकि वित्त वर्ष 2020–21 में 51.52 दिन और वित्त वर्ष 2021–22 में 50.07 दिन रोजगार मिला था।

जिन परिवारों को मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार वर्ष भर में पूरे 100 दिन रोजगार मिला, उनकी संख्या भी साल–दर–साल घटती जा रही है। वित्त वर्ष 2020–21में 71.97 लाख परिवारों को वर्ष भर में 100 दिन रोजगार मिला; वित्त वर्ष 2021–22 में ऐसे परिवारों की संख्या घट कर 59.14 लाख और वित्त वर्ष 2022–23 में और भी घट कर 36.01 लाख रह गई।

प्रधानमंत्री के ''मन की बात'': आडम्बर और पाखंड का नाटक

आर.एस. यादव

30 अप्रैल को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित प्रधानमंत्री के ''मन की बात'' कार्यक्रम इस सिलसिले की 100वीं कड़ी था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने तीन अक्टूबर 2014 को ''मन की बात'' कार्यक्रम की शुरूआत की थी जिसके माध्यम से वह हर महीने के आखिरी रविवार को विभिन्न मुद्दों पर लोगों के साथ अपने विचार साझा करने के नाम पर अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं। उनके ''मन की बात'' कार्यक्रम को आडम्बर और पाखंड के नाटक के सिवा और कोई नाम नहीं दिया जा सकता।

''मन की बात'' की 100वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि उनके लिए महज एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विश्वास और आध्यात्मिक यात्रा का विषय है। उन्होंने कहा, यह कार्यक्रम कोटि–कोटि भारतीयों के मन की बात है। इस विषय से जुड़ा वह जन आंदोलन बन गया और लोगों ने इसे जन आंदोलन बना दिया।'' प्रधानमंत्री ने ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'', ''स्वच्छ भारत अभियान'', ''आजादी का अमृत महोत्सव'', ''खादी को लोकप्रिय बनाने'' और ''प्रकृति से जुड़े कार्यक्रमों'' का उल्लेख किया।

''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' अभियान का खासतौर पर उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह बात भी घर–घर तक पहुंची।

जिस समय प्रधानमंत्री ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' अभियान का इस तरह उल्लेख कर रहे थे, क्या वह भूल गए कि अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाली पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और वे पिछले कई महीने से उनकी सरकार से गुहार लगा रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए?

क्या यह भारत के लिए और सरकार के लिए कलंक की बात नहीं है कि उनकी शिकायत के महीनों बाद भी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वह 23 अप्रैल 2023 से देश की राजधानी में जंतर–मंतर पर आकर बैठी हैं, तो भी मोदी सरकार अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय अपनी पूरी ताकत के साथ अपराधी को बचाने में लगी है? क्या साक्षी मलिक और विनेश फोगाट भारत की बेटियां नहीं?

जो प्रधानमंत्री अपने ''मन की बात'' कार्यक्रम में ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' अभियान का जिक्र करते हैं, उनकी सरकार साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की शिकायत पर जिस तरह का रवैया अपना रही है, क्या यह उनके स्वयं के लिए शर्म की बात नहीं?

हद तो यह है कि जिस मामले में शिकायत मिलते ही कानून की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, पुलिस को एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और शिकायतकर्ताओं को महज इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा कि मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि मोदी राज में ''कानून के शासन'' का गंभीर क्षरण हो रहा है?

सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद ही 28 अप्रैल 2023 को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। लेकिन फिर भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया।

''काफी जद्दोजहद के बाद 28 अप्रैल 2023 को दिल्ली पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और धमकी देने के आरोपों पर वह प्राथमिकी दर्ज करेगी। गौरतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के संदर्भ में अब तक कार्रवाई न होने की स्थिति में महिला पहलवानों को आंदोलन तक का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। हालांकि कुछ समय पहले जनवरी में भी पीड़ितों की ओर से पहली बार इन आरोपों के साथ सार्वजनिक रूप से अपना विरोध और दुख जाहिर किया गया था। मगर तब केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से उचित कार्रवाई सुनिश्चित कराए जाने के आश्वासन पर महिला पहलवानों ने अपना विरोध वापस ले लिया था। लेकिन विडम्बना यह है कि तीन महीने के बाद फिर दिल्ली के जंतर–मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करना पड़ा। जब उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर के उनके अनुरोध पर तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर कहा कि मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया है, तब जाकर अदालत को प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बारे में सूचित किया गया।

''जाहिर है, पुलिस ने अब जिन शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही, उनके कानूनी रूप से ठोस आधार थे। सवाल है कि आखिर क्या कारण रहे कि इस मसले के उठने के बाद से ये आधार मौजूद होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू करने में इतना लंबा वक्त लगाया। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में शिकायत सामने आने पर संवदेनशील तरीके से कार्रवाई करने के बजाय पुलिस की ओर से यहां तक कहा गया कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले आरोपों की जांच करने की जरूरत होगी। क्या पुलिस इस तरह की सभी शिकायतों के मामले में ऐसा ही मानदंड अपनाती है? अगर कानून सबके के लिए बराबर है, तो अलग–अलग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सक्रियता के पैमाने अलग–अलग क्यों हो जाते हैं? क्या यह अपने आप में आरोपी को बचाने की कोशिश और कानून के शासन को सवालों के कठघरे में खड़ा करना नहीं है? यह बेवजह नहीं है कि इस समूचे मामले में पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं कि वह पद और कद को देख कर कार्रवाई का स्तर तय करती है। (जनसत्ता, 29 अप्रैल, 2023)

एक अकेला यह मामला ही यह साबित करने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री के ''मन की बात'' कार्यक्रम में ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' जैसे अभियान की चर्चा करना एक आडम्बर और पाखंड है।

''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' जैसी प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी को बिलकिस बानो मामले में मोदी सरकार के रवैये से भी समझा जा सकता है। 2002 के गुजरात दंगों के समय बिलकिस बानो और उसके परिवार के साथ जो कुछ हुआ वह एक कलंक कथा बन चुका है, देश के लिए भी और देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी। बिलकिस के साथ बलात्कार किया गया उसके परिवार के एक दर्जन से अधिक सदस्यों को मार डाला गया और हत्यारों ने उसकी मासूम बच्ची को भी कत्ल कर दिया। गुजरात की तत्कालीन भाजपा सरकार ने हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही उन दरिन्दों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और अदालत ने मुल्जिमों को सजा सुनाई।

देश यह देखकर स्तब्ध रह गया कि पिछले दिनों गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार की सहमति के साथ इन दरिन्दों को सजा में छूट दे दी और उन्हें समय से पहले जेल से रिहा कर दिया।

''अपराध और दंड के संदर्भ में एक मशहूर उक्ति का उल्लेख अक्सर किया जाता रहा है–''न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि वह होते हुए दिखना भी चाहिए।'' विडम्बना यह है कि कई बार किसी अपराध के साबित हो जाने के बाद सजायाफ्ता दोषियों के बारे में भी सरकारों का रुख ऐसा होता है, जो समूची न्याय की अवधारणा को ही कठघरे में खड़ा कर देता है। जाहिर है, न्याय में भरोसा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक असहज करने वाली स्थिति होती है। शायद यह वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार (18अप्रैल 2023) को गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए यह कहा कि जब समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले जघन्य अपराधों की सजा में छूट पर विचार किया जाता है तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने जो सख्त टिप्पणियां की हैं, वह न्याय के संदर्भ में सरकारी रवैये को आईना दिखाने जैसा है।

''दरअसल, इस मामले में न सिर्फ एक गर्भवती महिला से सामूहिक बलात्कार किया गया, बल्कि उसके सात रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हमने गुजरात सरकार को इस संबंध में सभी साक्ष्य पेश करने के लिए कहा था....हम जानना चाहते हैं कि क्या गुजरात सरकार ने अपना विवेक लगाया है; अगर हां, तो बताएं कि आपने किस सामग्री को दोषियों की रिहाई का आधार बनाया है। हैरानी की बात यह है कि अदालत में गुजरात सरकार ने उम्रकैद के सजायाफ्ता दोषियों की रिहाई से जुड़े दस्तावेज दिखाने के आदेश का विरोध किया। जबकि अगर सरकार इस मामले पर खुद को सही मानती है तो उसे कम से कम अदालत के कहने पर पूरी पारदर्शिता जरूर बरतनी चाहिए। स्वाभाविक ही गुजरात सरकार के इस रुख पर अदालत ने एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए तो इस मामले में कोर्ट की अवमानना के आरोप में कार्यवाही चल सकती है और अगर कारण नहीं बताए जाते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकाल लेंगे। सवाल है कि इतने संवेदनशील मामले में सभी दोषियों की रिहाई का फैसला करने से पहले सरकार को क्या अपने विवेक का प्रयोग करना जरूरी नहीं लगना चाहिए था?

''गौरतलब है कि बिलकिस बानो के मामले में बलात्कार और हत्या की जैसी प्रकृति थी, उसकी गंभीरता के मद्देनजर सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इस मामले के सभी ग्यारह दोषियों को पिछले साल पंद्रह अगस्त को रहा कर दिया गया था। रिहाई के बाद सार्वजनिक रूप से इन सबका स्वागत करने की जैसी खबरें आई थीं, उसे लेकर बहुत सारे लोगों के बीच उचित ही दुख और आक्रोश फैला था। सवाल है कि ऐसा करके इस जघन्य अपराध की पीड़िता और उनके परिजनों के साथ–साथ न्याय में भरोसा रखने वाले सभी लोगों को किस तरह का संदेश दिया गया था? एक प्रश्न यह भी है कि ऐसी रिहाई का व्यापक सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा? इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की चिंता को समझा जा सकता है कि आज यह बिलकिस के साथ हुई घटना का सवाल है, कल ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सामूहिक बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के दोषियों के प्रति कोई सरकार नरम रवैया अख्तियार करती है, मगर इससे न्याय की धारणा को चोट पहुंचती है।'' (जनसत्ता, 20 अप्रैल 2023)

भाजपा हटाओ, देश बचाओ

जारी है जन जागरण पदयात्राओं का सिलसिला

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 14 अप्रैल से 14 मई 2023 तक देश व्यापी पदयात्रा भाजपा हटाओ – देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ आव्हान के तहत देश के विभिन्न राज्यों, जिलों में पदयात्राओं के अभियान जारी हैं।

पानीपत (हरियाणा)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 'भाजपा सरकार हटाओ–देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ' के नारे के साथ देशव्यापी राजनीतिक अभियान के तहत 30 अप्रैल 2023 को पानीपत में जन जागरण अभियान में शोंदापुर, खुकराना, आसन कला, आसन खुर्द, खन्डरा, शेरा, बाल जाटान, धर्मगढ़, रेर कला, कवी, मडलोडा, वेसर वेसरी, लुहारी सुताना, शोंदापुर आदि गांवों में भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया। आज के प्रचार जत्थे का नेतृत्व सीपीआई के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप ने किया और जिला सचिव पवन कुमार सैनी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य राम रतन एडवोकेट, हरपाल सिंह कश्यप, चंद्र भान निम्बरी, रामबीर कश्यप, भूल्लण, जय भगवान दरियापुर, भूपेन्द्र कश्यप, रुपेश सैनी बिन्दर सिंह तोमर आदि शामिल रहे।

इस दौरान दर्जनों नुक्कड मीटिंग की गई और पर्चे बांटे गये। नुक्कड मीटिंगों को दरियाव सिंह कश्यप, पवन कुमार सैनी, राम रतन एडवोकेट सहित अन्य ने सम्बोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि देश की आजादी और स्वतंत्रता के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अनेक संघर्षों में भाग लिया और देश के विकास के लिए संसद तथा संसद के बाहर अविस्मरणीय भूमिका अदा की। कम्युनिस्ट नेताओं ने कहा कि आज की भाजपा सरकार देश की मेहनतकश जनता द्वारा संघर्षो एवं बलिदानों से प्राप्त किये गए अधिकारों को कुचल रही है। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार देश के संविधान, लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही है। राम रतन एडवोकेट, पवन कुमार सैनी आदि ने नुक्कड़ मीटिंगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नव उदारवादी नीतियों के कारण देश व प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कम्युनिस्ट नेताओं ने कहा कि देश के मजदूरों, किसानों, दलितों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। वक्ताओं ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जन जागरण अभियान को समर्थन देने की अपील की।

29 अप्रैल

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 'भाजपा सरकार हराओ–देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ' के नारे के साथ देशव्यापी राजनीतिक अभियान के तहत आज 29 अप्रैल को पानीपत में जन जागरण अभियान शुरु किया गया। सीपीआई के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप ने पार्टी का झंडा दे कर प्रचार जत्थे को पार्टी कार्यालय भगत सिंह स्मारक पानीपत से रवाना किया। आज के जत्थे में हरियाणा किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष माम चंद सैनी, सीपीआई के जिला सचिव पवन कुमार सैनी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य राम रतन एडवोकेट सहित अशोक पंवार, हरपाल सिंह कश्यप, चंद्र भान निम्बरी, रामबीर कश्यप, भूल्लण, ओम प्रकाश, भूपेन्द्र कश्यप, कुलदीप सिंह आदि पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रचार जत्थे ने दरियापुर, उरलाना खुर्द, उरलाना कला, सींक, छिछडाना, अहर कालका, भादड़, सोदापुर कलौनी, जाटल रोड़ आदि गांवों व कालौनियों में नुक्कड़ मीटिंग करके पार्टी का जन जागरण अभियान चलाया। इस दौरान माम चंद सैनी, राम रतन एडवोकेट, पवन कुमार सैनी आदि ने नुक्कड़ मीटिंगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नव उदारवादी नीतियों के कारण देश व प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कम्युनिस्ट नेताओं ने कहा कि देश के मजदूरों, किसानों, दलितों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। पानीपत में अभियान 15 मई तक चलाया जायेगा।

ग्वालियर

ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

ग्वालियर जिला भाकपा सह सचिव एवं राज्य कार्यकारणी सदस्य कौशल शर्मा एडवोकेट, ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नौ वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व मे पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालो से पैदा हुये जन असंतोष की लहर पर सवार होकर सत्तासीन हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान जनता को 'न खाउंगा न खाने दूंगा' के भ्रष्टाचार विरोधी नारे के साथ, हर साल दो करोड़ रोजगार, हर व्यक्ति को पंद्रह लाख रुपये, किसानों की आय दुगनी करने के सब्ज बाग दिखाए गये थे। दावा 'सबका साथ सबका विकास का किया गया था' लेकिन अब जब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने को है, देश की मेहनतकश जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। देश मे सत्तर साल कुछ नही हुआ और जो कुछ हुआ वह पिछले नौ साल मे हुआ यह दावा करने वाली सरकार की कुल उपलब्धि यह है कि देश के 80 करोड़ लोग पांच किलो राशन के लिए राशन दुकान के सामने लाइन लगाये खड़े हैं। रोजगार के अवसर बढ़ने की जगह घट गये हैं और मोदी जी पकौड़ा बेचकर रोजी रोटी कमाने की सलाह दे रहे हैं। पिछले नौ साल मे करीब बीस करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिए गये हैं। आज गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक सुरक्षा , महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, के विश्व मानकों मे भारत सबसे निचले पायदान पर है और इसमे निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है। मोदी सरकार के हर कदम ने जनता के ऊपर और अधिक अत्याचार और आर्थिक बोझ को बढाने का काम किया है चाहे वह नोटबंदी हो या कोरोना काल मे सरकार के नकारेपन के कारण हुई हैं लाखों मौतें।

भाकपा कजरा शाखा लखीसराय (बिहार)

30 अप्रैल 2023 को जिला सचिव हर्षित यादव के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने पदयात्रा में शामिल होकर कोडासी के प्रत्येक गांव में जाकर भाजपा हटाओ, देश बचाओ जन सत्याग्रह जेल भरो आंदोलन के तहत लोगों को जागरूक किया एवं 8 एवं 9 जून को लखीसराय जिला समाहरणालय पर जन सत्याग्रह जेल भरो अभियान मेंअधिक से अधिक संख्या मे शामिल होकर अपनी जन समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपने हक और अधिकार की मांग करने की अपील की।

मागें निम्न प्रकार है:

1. राशन सब्सिडी को चालू किया जाए।
2. देश में बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए।
3. किसानों का कर्जा माफ किया जाए, समय पर खाद, और बीज, पानी, दिया जाए एवं उसका बीमा लागू किया जाए।
4. बढ़ती महंगाई पर रोक लगायी जाए।
5. भ्रष्टाचार पर पूर्ण रोक लगाया जाए।
6. सरकारी संस्थान को निजीकरण पर रोक लगाया जाए।
7. न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी देशवासियों के निशुल्क किया जाए।
8. सभी सरकारी जन कल्याण योजनाओं की जांच करायी जाए।
9. जाति और धर्म के नाम पर दंगा करवाना बंद किया जाए।
10. गरीब मजदूरों के लिए अलग से कानून बनाया जाए।
11. संविधान के साथ छेड़छाड़ करना बंद किया जाए आदि।

महिला पहलवानों पर पुलिसिया हमले की निन्दा

नई दिल्लीः भारतीय महिला फेडरेशन दिल्ली, पिछली रात जंतर–मंतर पर दिल्ली पुलिस की हरकतों की कड़ी निंदा करती है। भारतीय महिला फेडरेशन का समर्थन शुरू से न्याय मांगती खिलाड़ियों के साथ रहा है। ज्ञातव्य है कि 12 दिनों से हमारे देश की गौरव, कुश्ती संघ की महिला खिलाड़ी न्याय की मांग को लेकर खुले आसमान के नीचे दिन–रात धरने पर बैठी हैं। यौनिक, मानसिक और जीवन को खतरा जैसे गंभीर आरोप इन लोगों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए हैं। दुख की बात है कि मेडल मिलने पर पीठ थपथपाने वाले प्रधानमंत्री इनकी तकलीफ महसूस नहीं कर रहे। भारतीय महिला फेडरेशन काफी लंबे समय से पीओएसएच और पोस्को जैसे कानून की सख्ती से लागू किए जाने की मांग करती रही है। सरकार की खोटी नीयत का सबूत इस बात से मिलता है कि आईओए जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में आईसीसी नहीं है, जिसकी वजह से आज खिलाड़ियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। वह बहुत शर्म की बात है कि पोस्को के तहत एफआईआर के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और न ही उसके खिलाफ कोई न्यायिक जांच शुरू हुई है। उसकी गिरफ्तारी और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से फौरन निलंबित करने की मांग हम एक बार फिर सरकार से करते हैं। न्याय की इस लड़ाई में भारतीय महिला फेडरेशन एक बार फिर धरने पर बैठी महिला पहलवानों का अपना पूर्ण समर्थन देती है। हमारे संगठन की राज्य इकाइयां भी इन महिलाओं के लिए न्याय की मांग उठा रही हैं।

दिल्ली प्रगतिशील लेखक संघ का राज्य सम्मेलन

नई दिल्लीः दिल्ली प्रगतिशील लेखक संघ का राज्य सम्मेलन 29 अप्रैल 2023 को एटक भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर व पूर्व डूटा अध्यक्ष नंदिता नारायण ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की, जबकि मुख्य अतिथि प्रलेसं के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विभूति नारायण राय थे।

दिल्ली प्रलेस के अध्यक्ष व पत्रकार रामशरण जोशी जी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का संचालन करते हुए प्रलेस दिल्ली की महासचिव फरहत रिजवी ने सब से पहले शोक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में हम से बिछुड़ने वाले लेखकों, फनकारों, बुद्धिजिवियों और समाजकर्मियों को इस मौके पर याद करना हमारा फर्ज है। खगेंद्र ठाकुर, अली जावेद, ईश मधु तलवार, अरुण पांडेय, फादर स्टेन स्वामी, स्वयं प्रकाश, प्रो. अकील रिजवी, प्रो. नामवर सिंह, मुशर्रफ आलम जौकी, तबस्सुम फातिमा, मंगलेश डबराल, शमुसुर रहमान फारूकी, तरन्नुम रियाज, रियाज पंजाबी, कमला भसीन, शमीम हनफी, विनोद दुआ, दानिश, सुनीत चोपड़ा, केशरी सिंह चिढ़ार आदि, और साथ ही पाकिस्तान में फैज के दोस्त जफरुल्लाह खाँ पोशनी और मशहूर शायर अमजद इस्लाम अमजद को याद करते हुए हम किसान आंदोलन में शहीद होने वाले संघर्षरत किसानों को भी याद करते हैं।

उनके सम्मान में दो मिनट का मौन धारण के बाद प्रलेस की कार्यकारी अध्यक्ष अर्जुमंद आरा ने वक्ताओं का स्वागत किया और फिर फरहत रिजवी ने प्रोफेसर नंदिता नारायण को "नयी शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप के निहितार्थ" विषय पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। नंदिता नारायण ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज सत्तापक्ष शिक्षा व्यवस्था को कठपुतली की तरह अपने इशारे पर नचा रहा है। पहले तो सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया गया और अब सरकारी विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे एडहाक प्रोफेसर जिन्होंने विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने में हमेशा सहयोग दिया, जब उनकी स्थायी नियुक्ति का समय आया तो 2018 में यूजीसी ने शिक्षक भर्ती के नियमों को परिवर्तित कर दिया और जहां इंटरव्यू को भर्ती में केवल 10 से 20 प्रतिशत मान्यता दी गई थी, अब उसे बदल कर 100 प्रतिशत कर दिया। इस तरह सत्तापक्ष द्वारा पहले से तय किये हुए लोग ही अब प्रोफेसर के रूप में विश्वविद्यालयों में नियुक्त किये जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालयों में अब अकादमिक बुद्धिजीवियों की जगह सियासतदानों, राज्यसभा सदस्यों और आरएसएस के प्रचारकों को आमंत्रित किया जा रहा है। अपने वक्तव्य में प्रोफेसर नंदिता ने भारत के भविष्य की तुलना जर्मनी के हिटलर शासन से की। उन्होंने बताया कि जुलाई 2020 में जब पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा था तभी यूजीसी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में एक और परिवर्तन कर सीयूईटी (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) लागू कर दिया। सीयूईटी के बारे में जानकारी के अभाव के कारण कई विद्यार्थियों ने न तो फॉर्म भरा और कोरोना के कारण न ही इसका कोई विरोध हो पाया। इससे लाखों विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में दाखिले से वंचित रह गए। समापन की ओर ले जाते हुए उन्होंने कहा कि हमें और आपको मिलकर सत्ता पक्ष के समक्ष मजबूती से खड़े रहना होगा और भारत के भविष्य को बचाने के लिए छात्र और शिक्षक संघों को मिलकर यह लड़ाई लड़नी होगी। सम्मेलन में शामिल लेखक व पत्रकार रामशरण जोशी जी ने भी नंदिता जी के वक्तव्य का अनुमोदन किया। सम्मेलन सम्मेलन के दूसरे सत्र में शामिल प्रलेस के सदस्य लेखकों ने अपने विचार रखे। चर्चा के बाद प्रलेस की कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. अर्जुमंद आरा ने अनेक प्रस्तावों का ड्राफ्ट पेश किया जिसे साथी राजीव कुमार शुक्ल ने पढ़ कर सुनाया और उन्हें सर्व सम्मति से पास किया गया। आखिर में सर्वसम्मति से निम्न पधाधिकारियों का चयन हुआः

संरक्षक के रूप में विश्वनाथ त्रिपाठी, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असद रजा, दिविक रमेश, गुरबचन सिंह भुल्लर, केवल गोस्वामी, रामशरण जोशी चुने गये। अध्यक्ष शंकर, उपाध्यक्ष भगवानदास मोरवाल, बलबीर माधोपुरी, फरहत रिजवी और महासचिव अर्जुमंद आरा बनी तो, अतिरिक्त महासचिव ज्ञानचंद बागड़ी, संयुक्त सचिव आसिफ नकवी, मीडिया सचिव प्रभात, आफताब आलम चुने गये। कार्यकारी समिति अशोक लाल, अशोक मिश्र, अतहर फारुकी, अजरा नकवी, द्वारिका प्रसाद चारुमित्र, फारूक बख्शी, गार्गी चक्रवर्ती, हसन अब्दुल्लाह, खुर्शीद अकरम, मनीष श्रीवास्तव, मीनाक्षी सौंद्रियाल, नवोदित, वर्षा आनंद चुने गये। ऐसे साथी जो दिल्ली के आस–पास रहते हैं या संगठन में सक्रिय रहे हैं, आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किये गए, जिसमें शामिल हैं, राजीव कुमार शुक्ल, सी सदाशिव, विनीत तिवारी, तारेन्द्र किशोर।

आगरा किसान सभा का जिला सम्मेलन संपन्न

आगराः अखिल भारतीय किसान सभा जिला आगरा का 23वां जिला सम्मेलन 30 अप्रैल 2023 को ईश्वर चंद इंटर कॉलेज मलपुरा में संपन्न हुआ। खुले अधिवेशन की अध्यक्षता संयुक्त रूप से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, महेंद्र सिंह (पूर्व प्रधान), जयपाल सिंह (प्रधान, गदौली), नत्थीलाल (मिस्त्री साहब, मालपुरा) और मोतीराम कुशवाह (गोराऊ) ने की।

सम्मेलन का उद्घाटन डॉ. जवाहर सिंह धाकरे (पूर्व प्राचार्य, आरबीएस डिग्री कॉलेज, आगरा) ने किया। डॉ. धाकरे ने अपने स्वागत भाषण में किसानों के हालात और अपने विदेश प्रवास के दौरान किसानों के बारे में जो जानकारी हासिल की उसके बारे में बताया। साथी ने किसान भाइयों से आने वाले समय में और संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए कहा।

मुख्य वक्ता अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के फलस्वरूप खेती में काम आने वाले डीजल, उर्वरकों, बिजली, बीज और फसल सुरक्षा रसायनों एवं मशीनरी की कीमतें आसमान छू रही हैं, किसान बेमौसम बारिश और प्राकृतिक प्रकोप झेलने को मजबूर है। उधर उनकी फसलों आलू, गेहूं, सरसों, आदि के लाभकारी मूल्य न मिलने से किसान समुदाय कर्ज के जाल में फंस कर आत्महत्या करने को विवश है।

जबकि मोदी सरकार द्वारा अदानी, अंबानी जैसे कारपोरेट मित्रों का दस लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ कर दिया गया है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष छीतर सिंह एडवोकेट ने मनरेगा के बजट में वृद्धि, प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को 200 मानव दिवस रोजगार की गारंटी, किसानों पर लगे मुकदमे वापस लेने, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की। मैनपुरी के किसान नेता राधेश्याम यादव ने किसानों की कर्ज माफी एवं 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिकों, सभी किसानों, खेत मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकारों को वृद्धावस्था पेंशन की गारंटी की मांग की।

किसान सभा अध्यक्ष भारत सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ किसान बदहाल है, युवा बेरोजगार और आम जनता भयंकर महंगाई की मार से त्रस्त है और दूसरी ओर जनता के बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी नेता और उनका आईटी सेल एवं गोदी मीडिया चुनावी स्वार्थ के चलते बहुसंख्यक समुदाय के वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू, मुस्लिम एवं मंदिर, मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। किसानों को इससे सावधान रहने और अपने मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।

इप्टा के राष्ट्रीय सचिव दिलीप रघुवंशी ने किसानों से अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य, युवाओं को रोजगार, महंगाई, निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ सेवाओं और बिजली जैसी बुनियादी सवालों के लिए संगठित होकर संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने की अपील की। सम्मेलन में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर 1 साल तक प्रत्येक माह भाग वाले साथियों को सम्मानित किया गया जिसमे भीकम सिंह कुशवाह, पूरन सिंह यादव, कोमल सिंह राजपूत, जयपाल सिंह, मोती राम कुशवाह शामिल थे। इप्टा के कलाकार योगेंद्र स्वरूप जी ने किसानों के हालात पर राजेंद्र रघुवंशी द्वारा लिखित गीत गाकर सुनाए। सम्मेलन में मुख्य रूप से भाकपा राज्य परिषद सदस्य ओम प्रकाश, भाकपा आगरा जिला मंत्री पूरन सिंह, वरिष्ठ नेता हरविलास दीक्षित, सहायक जिला मंत्री धर्मजीत, भाकपा जिला कार्यकारिणी सदस्य नीरज मिश्रा और महिला फेडरेशन से निशा राठौर आदि उपस्थित थे। अखिल भारतीय किसान सभा के 23वें जिला सम्मेलन में 25 सदस्यीय जिला कमेटी का चुनाव किया गया तथा भीकम सिंह कुशवाहा को जिला अध्यक्ष, जयपाल सिंह यादव एवं बंगाली कुशवाहा को जिला उपाध्यक्ष तथा पूरन सिंह यादव को जिला मंत्री एवं ब्रजकिशोर व रामभरोसी को सहायक मंत्री और पूरनसिंह को सर्वसम्मति से कोषाध्यक्ष चुना गया। साथ ही जगदीश प्रसाद शर्मा, ओमप्रकाश प्रधान, कोमल सिंह, नारायन सिंह सहित दस प्रतिनिधि राज्य सम्मेलन के लिए चुने गए।

दूरदृष्टा, यायावर विद्रोही, प्रेम भावना तथा विश्वबंधुत्व के प्रसारक

स्वाभाविक वामपंथी थे राजा महेन्द्र प्रताप सिंह

डॉ. गिरीश

राजा महेन्द्र प्रताप जैसे महान व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में समाज और इतिहास दोनों ने चूक की है। इतना ही नहीं उनके धुर दक्षिणपंथी विरोधी भी वोटों की राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल समय समय पर करने से चूकते नहीं हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर पसरा सन्नाटा हैरान करने वाला है। जन्मदिवस भी अधिकतर उनके सजातीय लोग और वामपंथी ही मनाते देखे जाते हैं। उन्हें साधुवाद ही दिया जाना चाहिए।

उनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को वर्तमान हाथरस जनपद में स्थित मुरसान रियासत में हुआ था और जिन्हें हाथरस के राजा श्री हरनारायन सिंह ने 3 वर्ष की उम्र में ही गोद ले लिया था। हाथरस के मुख्य किले और उसके राजा दयाराम का पतन अंग्रेजों के हाथों 1857 में ही हो चुका था। संबन्धित छोटी छोटी कई रियासतों के उत्तराधिकारीगण हुकूमत से प्राप्त जमींदारियों से जीवनयापन कर रहे थे।

विद्रोही स्वभाव के राजा महेंद्र प्रताप को गुलामी जैसी यह व्यवस्था स्वीकार न थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो तब एंग्लो मुहम्मडन कालेज था, से बीए की शिक्षा ग्रहण करने के वक्त ही वे आजादी के आंदोलन से जुड़ने लगे और 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने जा पहुंचे। आजादी के पावन उद्देश्य से उन्होने लेखन किया, पत्रकारिता की और अंततः देशभक्त योद्धा बन कर उभरे।

इसी बीच उनका विवाह राजस्थान के जींद की राजकुमारी बलबीर कौर से हुआ। मगर विद्रोही, यायावर और 32 साल तक निर्वासित जीवन बिताने के चलते परिवार को बहुत अधिक समय नहीं दे सके। बताया जाता है कि उनकी दो प्रिय पुत्रियों के निधन के समय पर भी वे देहरादून आवास पर मौजूद न थे।

इसे उनकी दूरदर्शिता ही कहा जायेगा कि सांप्रदायिक–वैमनस्य को वे देश की जनता का सबसे बड़ा शत्रु समझते थे। वे प्रेम और भाईचारे की ताकत को समझते थे, अतएव प्रेमधर्म प्रारंभ किया। उसे मूर्त रूप देने और शिक्षा की महत्ता को ध्यान में रखते हुये उन्होने 1909 में वृन्दावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की। इसके शुभारंभ के अवसर पर स्वयं महामना मदन मोहन मालवीय जी उपस्थित थे। वहीं एक प्रेम पोलिटेकनीक भी खोला गया जो विज्ञान और तकनीकी के प्रति उनके दृष्टिकोण का परिचायक है।

बसुधेव कुटुम्बकम की भावना से ओतप्रोत उन्होने प्रथम विश्वयुद्ध के समय से ही "संसार संघ" की परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया था। यह कुछ कुछ सर्वहारा के अंतर्राष्ट्रीयतावाद से प्रेरित था।

अंग्रेजी हुकूमत ने उनको संपत्तियों से बेदखल कर रखा था। उससे पहले अलीगढ़ और हाथरस की कई शिक्षण संस्थाओं को उन्होने जमीनें दान कीं। वर्तमान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भी उन्होने 3 एकड़ जमीन दी। 1911 में आर्यसमाज सभा को 80 एकड़ जमीन दान दी। आज वोट के लिए कट्टरपंथी लोग उनको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर हमले बोलते रहते हैं, लेकिन आर्यसमाज सभा को दी गयी जमीनों का क्या हुआ, कभी कोई नहीं बोलता।

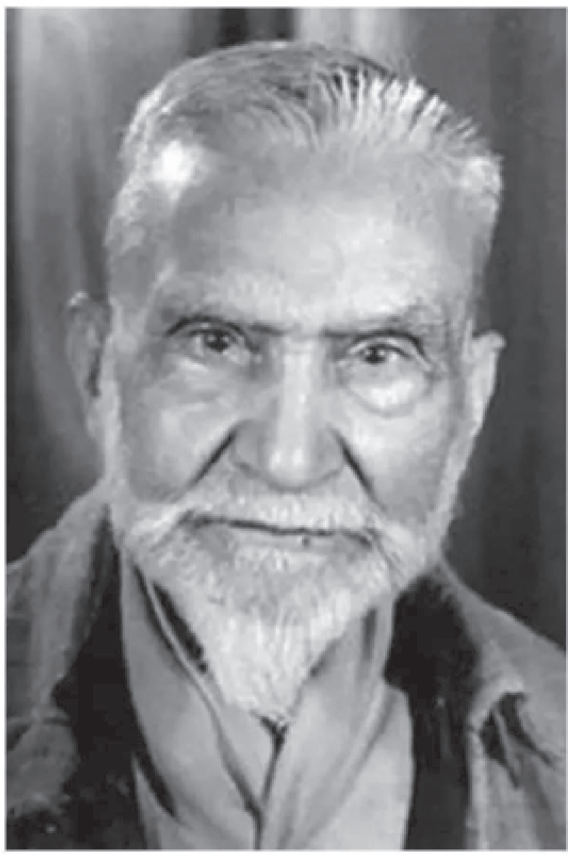

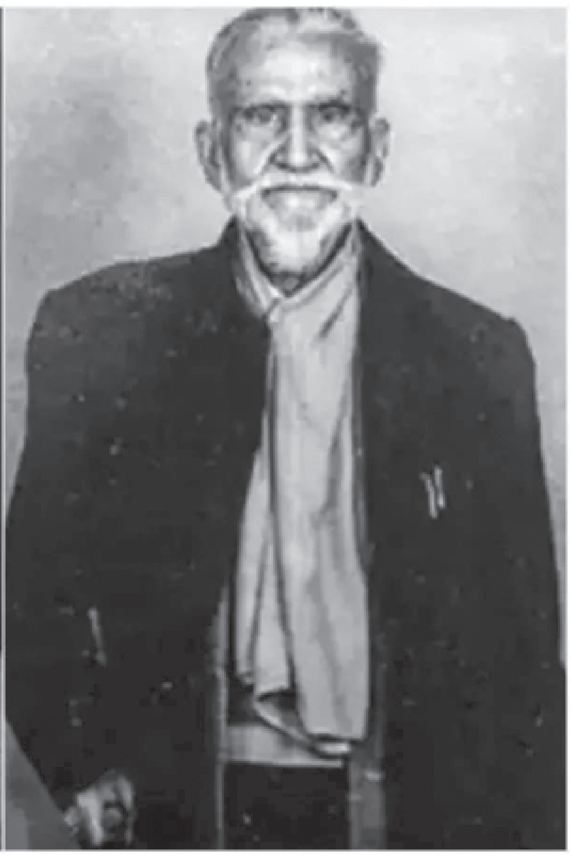

देश को अंग्रेजी दासता से मुक्त कराने का जुनून उन्हें सीमाओं के पार ले पहुंचा और 1914 में यूरोप के रास्ते वे काबुल पहुँच गए। वहां 1 दिसंबर 1915 को भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया जिसके वे राष्ट्रपति बने। श्री बरकतुल्लाह खान को प्रधानमंत्री बनाया गया।

निर्वासित सरकार बनाने के उनके इस कदम का यह कहते हुये मजाक बनाया गया कि वे काल्पनिक स्वप्नदर्शी हैं। आखिर इस सरकार का क्या मतलब? लेकिन इस सरकार के मतलब थे– भारत की जनता का विश्वास जगाना और अंग्रेजों को चुनौती पेश करना कि भारत की अपनी सरकार अब अस्तित्व में आ गयी है। आखिर भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने भी तो नेशनल असेंबली में बम इन्ही उद्देश्यों के लिए फेंका था, हिंसा अथवा खून खराबे के लिए नहीं।

1917 में रूस में कामरेड लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक (कम्युनिस्ट) पार्टी द्वारा जारशाही का तख्ता पलट दिया गया था और रूसी समाजवादी क्रान्ति हो चुकी थी। शोषण से मुक्त मेहनतकशों के राज्य के नवनिर्माण की कोपलें फूट रहीं थीं। भारत के तमाम क्रांतिकारियों को इस क्रान्ति ने आकर्षित किया था। राजा महेन्द्र प्रताप भी उनमें से एक थे। वे पेट्रोग्राद (बाद का लेनिनग्राद) जा पहुंचे और महान लेनिन से भेंट की। बताते हैं कि उन्होने लेनिन से भारत की आजादी के आंदोलन में हस्तक्षेप का आग्रह किया। लेनिन ने उन्हें समझाया कि किसी भी देश का राष्ट्रीय आंदोलन प्राथमिक तौर पर उसके अपने लोगों द्वारा चलाया जाना चाहिये। आप वहां तैयारी कीजिये, हम नैतिक समर्थन देते हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व वाली अस्थाई सरकार के एक प्रतिनिधि एम पी टी आचार्य थे जिनके प्रतिनिधि ने ताशकंद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से एक ग्रुप बनाने में योगदान किया था।

उन्हें 1932 में शान्ति के नोबल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था।

1946 में तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों से वे भारत आये। जगह जगह उनके स्वागत समारोह हो रहे थे। देश आजाद हो चुका था, मगर उनके स्वागतों का सिलसिला थम नहीं रहा था। तब हाथरस अलीगढ़ जनपद में हुआ करता था। अलीगढ़ के धर्म समाज कालेज में भी एक स्वागत समारोह रखा गया था। उनके मन में एक हिन्दू मुस्लिम भाईचारे से ओतप्रोत भावी भारत की कल्पना हिलोरें ले रही थी। उन्होने अपने भाषण में कहा कि अब देश आजाद है–कोई भी भाई बहन किसी भी धर्म के मानने वाले से शादी कर सकता है। उनके यह कहते ही वहां मौजूद सांप्रदायिक तत्व फुफुकार उठे और उनके ऊपर ईंट–पत्थर फेंकने लगे। प्रशासन ने बंद गाड़ी में बैठा कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। यह घटना बचपन में हमारे पिता श्री शिव नन्दन शर्मा ने बताई थी जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। आज वे ही सांप्रदायिक तत्व उनको वोट की फसल उगाने में इस्तेमाल कर रहे हैं।

1957 के लोकसभा चुनाव में वे मथुरा संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी हुये। जनसंघ से श्री अटल बिहारी बाजपेयी लड़े और चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस से दूरी और अपने एजेंडे पर ही चलने वाले राजा महेन्द्र प्रताप को उस समय की राजनीति ने खपाया नहीं या वे खपे नहीं। 1962 का मथुरा से लोकसभा चुनाव हारने के बाद सामाजिक कामों तक ही सिमट गए।

महापंडित राहुल सांकृत्यायन तब मसूरी में निवास कर रहे थे। 8 अक्तूबर 1955 को राजा महेन्द्र प्रताप उनसे मिलने पहुंचे। यह उस महान देशभक्त के व्यक्तित्व के महापुरुषों के प्रति भाव को दर्शाता है। राहुल जी ने भी इस महान देशभक्त के आगमन को भारी महत्व दिया और अपनी आदत के मुताबिक डायरी में नोट कर दिया। वह इस प्रकार है–

स्वतन्त्रता संघर्ष के जीवित शहीदों की वह ज्वलंत मूर्ति हैं। मैं समझता था कि 70 के ऊपर के होंगे, लेकिन अभी उम्र 68 की ही थी। स्वास्थ्य इस अवस्था में जैसा होता है, उसे देखते हुये बुरा नहीं था। "संसार संघ" की धुन उन्हें वर्षों पहले से ही है। जानते हैं बात सुनने वाले भले ही मिलें, लेकिन मानने वाले नहीं मिलते। तो भी उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी में अपने "संसार संघ" को निकालते ही जा रहे हैं।,,,,,,,,,

वह प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ हैं। राज रियासत छोड़ कर बेसरो सामानी के देश से निकल गए। अंग्रेजों के कुत्ते उनके पीछे पड़े रहते। सगे संबंधी उनकी गंध से भी डरते। पर वह आजीवन अपने विचारों पर डटे रहे। अंग्रेजों के प्रति उनकी अपार घृणा कभी नहीं घटी। कई बार उन्होने पृथ्वी की परिक्रमा की।,,,,,,

ऐसे पुरुष की जीवनी कितनी प्रेरणादायक होगी, सोच कर मन होता है, उसे लिख डालूं।,,,,,,, उनके पैरों में अब भी चक्का बंधा हुआ है। (राहुल जी– मेरी जीवन यात्रा, जिल्द 4 पृष्ठ 224– 25, नया संस्करण, पेपर बैक)

29 अप्रैल 1979 को इस महान देशभक्त ने इस नश्वर शरीर का परित्याग किया। तत्कालीन भारत सरकार ने उन पर एक डाक टिकट जारी किया था। अब जनता की वर्षों से चली आ रही मांग पर अलीगढ़ में उनके नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

वामपंथी राष्ट्रपति के पुनः सत्तारूढ़ होने के बाद ब्राजील में हक–हकूक की लड़ाइयों ने गति पकड़ी

डॉ. गिरीश

राजसत्ता पर जब लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील अथवा वामपंथी शक्तियां काबिज होती हैं तो हक और हकूक की लड़ाइयाँ तेज होती हैं और लोग रोजी, रोटी तथा अधिकार प्राप्त करने के संघर्षों को आगे बढ़ाते हैं। सत्ता पर जब तानाशाह, क्रूर और निजस्वार्थपरक शक्तियां काबिज होती हैं तो हक–हकूक की लड़ाइयाँ को कुचल कर धर्म, जाति, संस्कृति और क्षेत्र के नाम पर टकरावों को आगे कर देती हैं।

वामपंथी राष्ट्रपति लूला डी. सिल्वा की जीत के बाद ब्राजील में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। गत दक्षिणपंथी राष्ट्रपति बोल्सोनारो की जनता के प्रति आक्रमणकारी नीतियों के चलते जनता के हितों के लिए लड़े जाने वाले संघर्ष थम गए थे, वे आज पुनः मुखरित होने लगे हैं।

ब्राजील एक ऐसा देश है जहां कृषि उद्योग बहुत ताकतवर है और अधिकतर जमीनों पर बड़े फार्म मालिकों का कब्जा है। फार्म लॉबी वहाँ की सत्ता पर सीधे नियंत्रण जमाती रही है। परिणामतः वहाँ भूमिहीनों की संख्या पर्याप्त है, जो भूमि पर भागीदारी पाने को लंबे समय से संघर्षरत हैं। बोल्सोनारो के सत्ता में रहते जो भूमि आंदोलन ठिठक गया था आज वह वामपंथी राष्ट्रपति लूला के पुनः सत्ता में आने के बाद परवान चढ़ना शुरू हो गया है। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत और तथ्यपरक रिपोर्ट 'द न्यूयार्क टाइम्स' के अभी हाल के अंक में प्रकाशित हुयी है।

न्यूयार्क टाइम्स लिखता है–

वे कुदाल, फाबड़ा, छुरी, हथौड़ा और हंसिया या दराती जैसे हथियार जैसे औजारों के साथ जमीन पर कब्जा करने के इरादे से पहुंचे थे। ये 200 एक्टिविस्ट और खेतिहर मजदूर जब वहां पहुंचे, तो घास–फूस और एक आवारा गाय को छोड़ कर पूरा फार्म खाली था। अब तीन महीने बाद यह एक चहल–पहल भरे गांव में बदल चुका है। हाल ही में बच्चों ने यहां के नये कच्चे रास्तों पर साइकिल चलाई, महिलाओं ने बगीचों के लिये मिट्टी खोदी और पुरुषों ने आश्रयस्थलों के ऊपर तिरपाल बिछाये।

करीब 530 परिवार पूर्वोत्तर ब्राजील के शहर इटाबेला की इस बस्ती में रहते हैं। वे आपस में घुलमिल गये हैं और उन्होने वहां सेम, मक्का और कसावा रोप दिये हैं। जिन भाई–बहनों को यह 370 एकड़ खेत विरासत में मिले थे, वे चाहते हैं कि वे अवैध कब्जाधारी वहां से चले जायें। मगर यहां के नये कब्जाधारियों का कहना है कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं।

इस डेरे के प्रभावी नेता 38 वर्षीय अलसियोनी मैनथे ने कहा, आजीविका, संघर्ष और टकराव की एक प्रक्रिया है। यदि कहीं आजीविका न हो, तो वहां कोई बस्ती भी नहीं होगी।

मैनथे और अन्य बिन बुलाये पदाधिकारी लैंडलेस वर्कर्स मूवमेंट का हिस्सा हैं, जो कि शायद दुनियां का सबसे बड़ा मार्क्सवादी– प्रेरित आंदोलन है और एक लोकतन्त्र के भीतर काम कर रहा है तथा 40 वर्षों के खूनी कब्जे के बाद ब्राजील में एक प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और सान्स्कृतिक ताकत बन गया है।

इस आन्दोलन ने ब्राजील के हजारों गरीबों को संगठित कर उन्हें अमीरों की अनुपयोगी जमीनो पर कब्जा कर बसने तथा सामूहिक खेती करने के लिये प्रेरित किया। वे कहते हैं कि वे ब्राजील में भूमि के असमान वितरण से उत्पन्न गहरी असमानता को उलट रहे हैं। वामपंथियों ने उनके उद्देश्य का समर्थन किया है, पर अनेक ब्राजीलवासी उन्हें कम्युनिस्ट और अपराधी की तरह देखते हैं।

इसने इस आन्दोलन के समर्थक नये राष्ट्रपति लूला डी. सिल्वा के लिये दुविधा पैदा कर दी है, जो कि अभी संसद और ताकतवर कृषि उद्योग के बीच समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

शोधकर्ताओं का अनुमान है कि अभी 4,60,000 परिवार लैंडलेस वर्कर्स मूवमेंट द्वारा शुरू किये गये शिविरों और बस्तियों में रहते हैं। वहां रहने वालों की संख्या 20 लाख के करीब पहुंच रही है, जो कि ब्राजील की आबादी का लगभग एक फीसदी के बराबर है। बोल्सोनारो के शासन में उनकी आक्रामक नीतियों के कारण आन्दोलन की गति फीकी पड़ गयी थी। पर अब लूला के चुनाव से उत्साहित आन्दोलन के सदस्यों ने जमीन पर कब्जे की मुहिम तेज कर दी है।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरनिकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिकाः भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फैज़ः प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज्बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरुदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मृखदूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाषः 011–23523349, 23529823
ईमेलः pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरुम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोनः 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोनः 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोटः आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरणः
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंटः 32074674284, आई.एफ.सी. कोडः SBIN0009371

मजदूरों का संकल्प : मजदूर विरोधी भाजपा सरकार को करेंगे अपदस्थ

पेज 1 से जारी...

होगा।

वक्ताओं ने भाकपा के जन जागरण अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि देश की आजादी और स्वतंत्रता के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अनेक संघर्षों में भाग लिया और देश के विकास के लिए संसद तथा संसद के बाहर अविस्मरणीय भूमिका अदा की। कम्युनिस्ट नेताओं ने देश की एकता–अखंडता की रक्षा के लिए संघर्षों के चलते अनेक बलिदान दिये। इन कार्यक्रमों में चन्द्रभान निम्बरी, भूपेन्द्र कश्यप, रुपेश सैनी, रामपाल सैनी, राज कुमार, नन्हा राम, सतीश कुमार, रमेन्द्र राय, भूल्लण राम सहित अनेक मजदूर शामिल हुए।

ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

प्रातः 9 बजे से ग्वालियर में शिकागो में शहीद हुए मजदूरों को याद करते हुए एवं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मई दिवस मनाया गया। ग्वालियर के प्रसिद्ध मजदूर नेता एवं पूर्व विधायक कामरेड रामचंद्र सरवटे के प्रतिमा स्थल सरवटे चौक हजीरा ग्वालियर पर इकठ्ठा होकर झंडा वंदन कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दुनिया के मजदूर एक हो, शिकागो के अमर शहीदों को लाल सलाम–लाल सलाम, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उत्साह से मजदूर दिवस मनाया गया।

भाकपा, ग्वालियर जिला सह सचिव एवं राज्य कार्यकारिणी सदस्य कौशल शर्मा ने बताया कि एटक, एक्टू, एआईयूटीयूसी एवं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल द्वारा मई दिवस के अवसर पर शाम 5 बजे छप्पर वाला पुल लश्कर ग्वालियर से विशाल रेली शहर के प्रमुख मार्गो से होती हुई निकाली, जो फूल बाग चौराहा ग्वालियर पर आम सभा के रूप में तब्दील हो गई। मई दिवस की आयोजित रैली में बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन के साथी महिला पुरुष और नौजवानों ने भारी संख्या में भाग लिया।

सिवनी

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) मजदूर यूनियन के तत्वाधान में कामगार यूनियन बहरइ एवं भवन निर्माण कामगार यूनियन बरघाट के तत्वाधान में बहरइ और बरघाट में बरघाट क्षेत्र के विधायक श्रीमान अर्जुन सिंह ककोडिया के मुख्य आतिथ्य एवं डीडी वासनिक, संरक्षक एटक यूनियन जिला सिवनी की अध्यक्षता में 1 मई को दोनों स्थान पर अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया।

इस अवसर पर रैली निकालकर पूरे बहराइ एवं बरघाट में भ्रमण करके सभा की गई जिसको बहरइ में मरार माली समाज के जिलाध्यक्ष राणा जी मनोज राहंग डाले, यीशु प्रकाश, ओम प्रकाश बोर्डे एवं किरण प्रकाश जिला सचिव महिला फेडरेशन सिवनी, एटक के जिलाध्यक्ष तीरथ प्रसाद गजभिए, जागेश्वर परते ने संबोधित किया। इसी तरह बरघाट में सभा को श्री अर्जुन सिंह ककोडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से यीशु प्रकाश महिला फेडरेशन की ओर से किरण प्रकाश, राजेश पारदी, सुरेंद्र गेराम, एटक के जिलाध्यक्ष तीरथ प्रसाद गजभिए एवं सभा के अध्यक्ष डीडी वासनिक ने संबोधित किया।

पूरे विश्व में सन 18 86 में अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों की 8 घंटे की मांग को लेकर की गई सभा में पूंजीपतियों की पुलिस द्वारा 8 मजदूरों की गोली चला कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी की याद में 1 मई मजदूर दिवस मनाया जाता है इसी कड़ी में सिवनी जिले में भी अनेक स्थानों पर एटक मजदूर यूनियन की ओर से अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया एवं जिले में कहीं भी मेहनतकश जनता पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया गया। इसी तरह शासकीय विभागों में काम करने वाले विभिन्न प्रकार के कर्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक, मध्यान भोजन कर्मी, काष्ठा गान मजदूर, भवन निर्माण मजदूर, वन सुरक्षा श्रमिक, अतिथि शिक्षक आदि की मांगों का समर्थन किया गया और अगले वर्ष फिर से मिलकर अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया।

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)

मजदूर दिवस भारद्वाज भवन के सरजू पाण्डेय सभागार में मनाया गया। दुनिया के शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि देने के उपरांत मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया था। अपने सम्बोधन में भाकपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य अमेरिका सिंह यादव ने कहा कि बड़ी कुर्बानी के बाद 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के, 8 घन्टे शिक्षा के अधिकार को मजदूरों ने प्राप्त किया था। परन्तु भारत सरकार इस पर हमला बोल रही है। श्रम कानून को पूंजीपतियों के पक्ष में कर रही है। निजीकरण तेज हो गया है। पेंशन बंद कर दी गई है। मजदूरों के बलिदान से प्रेरणा ग्रहण करके जन विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करना होगा। जिला सचिव जनार्दन राम ने कहा कि यह सरकार केवल मजदूरों पर ही हमला नहीं कर रही है। अपितु किसान, असंगठित मजदूरों, छात्रों, बेरोजगारों, महिलाओं, कर्मचारियों पर कुठाराघात कर रही है। स्वाधीनता आंदोलन एवं उसके बाद देश की सारी उपलब्धियों को मटियामेट कर रही है। इतना ही नहीं संविधान को तिलांजलि देकर अवैज्ञानिक विचारों, जातिवादी, सांप्रदायिक विचारों को प्रश्रय दे रही है। देश में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बनाये और बचाये रखने के लिए व्यापक एकता कायम करके वर्तमान सरकार को सत्ता से बाहर करना समय की मांग है। इसमें सह सचिव ईश्वर लाल, डॉक्टर रामबदन सिंह, सुरेंद्र राम, रामशुक्ला, रामलाल, डॉक्टर इकबाल अंसारी, फूल मैन, श्यामा प्रसाद, रामराज बिंद आदि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये। अध्यक्षता एवं संचालन रामावध ने किया।

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

सभी श्रमिक संगठनों के संयुक्त आह्वान पर बिलासपुर में मेहनतकश जनता ने बढ़–चढ़कर मई दिवस में भागीदारी की। सर्वप्रथम भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी जिला परिषद इकाई बिलासपुर तोरवा पुराना पावर हाउस से विशाल रैली चलकर, गुरुनानक चौक, जगमल चौक, गोलबाजार होते हुए राघवेन्द्र राव सभा भवन, कंपनी गार्डन बिलासपुर में आम सभा में बदल गई। सभा की अध्यक्षता ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष पी आर यादव ने किया और केन्द्र सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी, कारपोरेट परस्त नीतियों, 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ, कड़े शब्दों मे विरोध प्रदर्शन किया गया। भाकपा जिला सचिव पवन शर्मा, नौजवान सभा के प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत शर्मा, लल्लन सिंह, रवि बनर्जी, महेश श्रीवास, नन्द कश्यप, नारायण चौधरी, राजेश शर्मा, संत निराला आदि ने आमसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को तानाशाही करार देते हुए किसान विरोधी मजदूर विरोधी जन विरोधी और कारपोरेट्स हितैषी सरकार बताया सभी वक्ताओं ने एक सुर में केंद्र सरकार से मांग की है कि मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं को तत्काल वापस लेना चाहिए।

इस सभा को सफल बनाने में मुख्य रूप से पवन शर्मा, भरत लाल धुरी, काशीराम ठाकुर, एच डी पाइक, उदयराम टंडन, सीपीआई माले से ललन सिंह, रेलवे से कन्हैया यादव, भैरव निषाद, शीलू सिंह, विक्रांत शर्मा, संत निराला, पावेल शर्मा, विनय शर्मा, दिलीप धुरी, विजय शर्मा, एडवोकेट लखन सिंह, पूनाराम धुरी, गुनाराम धुरी, दिलीप धुरी, रमा शर्मा, कमला नागपुरे, सुलोचना सिंह, लक्ष्मी साहू, भूरी बाई, सती बरगाह, कौशल्या बाई, बसंत दुबे, अवधेश पटेल, रवि शर्मा, पवन शर्मा, साधूराम धुरी, ईश्वर वस्त्रकार, सोमनाथ निषाद, गोकुल ठाकुर, राजू लोधी, सूरज लोधी, बिल्लू, बिंदास, मंत रामधुनी, साधु राम दूरी, सुनीति शर्मा, यशोदा शर्मा, सविता शर्मा, लखन सिंह एडवोकेट, मोनू निषाद, लक्ष्मी देवी शर्मा, सुनीता निषाद और राजकुमारी, केवट चिल्लू सिंह, सुरेश लांजेकर, मनसाराम ठाकुर, बहोरन कहर, रामनारायन कुर्मी, प्रमोद मसीह, विजय नेताम, धीरज शर्मा, अमृत सिंह आदि उपस्थित रहे।

झालावाड़ (राजस्थान)

जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल झालावाड़ के महासचिव महेंद्र कुमार जैन ने बताया कि रोडवेज बस स्टैंड परिसर में विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने सोमवार को मजदूर दिवस मनाया।

इस मौके पर कर्मचारी नेताओं ने सरकार की जनविरोधी नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध किया कार्यक्रम की शुरुआत कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष राधेश्याम पंकज ने झंडारोहण कर किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए काउंसिल के जिला अध्यक्ष एडवोकेट बच्चू लाल ने सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करते हुए कर्मचारियों को भी विरोध के लिए प्रेरित किया एआईबीईए इकाई झालावाड़ के सचिव महेंद्र जैन ने शिकागो में मजदूर आंदोलन के दौरान शहीद हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को नमन किया।

आरएसआरटीसी रिटायर्ड एसोसिएशन के प्रदेश सचिव राजकुमार जैन व केंद्र व राज्य सरकारों की श्रमिक विरोधी नीतियों का बहिष्कार करते हुए राजनीतिक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया साथ ही उपस्थित साथियों का आभार माना। रिटायर्ड एसोसिएशन क्षेत्रीय सचिव लाल संगीत में मंच संचालन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारी बैंक एसबीआई एलआईसी रोडवेज के विभिन्न उपस्थित रहे इस मौके पर आशीष पाल सिंह ,राकेश शर्मा, आर के लाहोटी, युवराज सिंह, त्रिभुवन, अंकेश मित्तल, लालचंद पंवार, सुनील कानावत, श्रीनाथ अब्दुल, अजीज बैग, महमूद अहमद, अब्दुल रहीम, प्रहलाद सेन, ब्रजराज सिंह, हबीब खान, इशाक खां, अयूब खान, रामस्वरूप सोनी, राजू लाल वैष्णव, अब्दुल हमीद ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया।

ऐतिहासिक चुनौतियों के दरमियान आज का मजदूर ...

पेज 7 से जारी...

मांगें हैं जो न केवल हमारे आधार को व्यापक करने में हमारी सहायता करेंगी और लोगों को हमारी ओर आकर्षित करेंगी बल्कि हमारे देश को एक बेहतर और समावेशी लोकतंत्र बनाने में भी सहभागी होंगी। 'किसान मजदूर एकता'– किसी भी देश मे मेहनतकश वर्ग की पूरी तस्वीर किसानों और मजदूरों को मिलाकर ही बनती है। हाल के वर्षों में किसानों ने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से जो जुझारुपन दिखाया है, वह श्रमिक संगठनों के लिये भी अनुकरणीय है। इसलिये यह प्रयास किया जाना चाहिए कि ये दोनों तबके एक साथ आकर जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष करें।

आज हमारे देश के ताने–बाने पर फासीवादी खतरा मौजूद है। एक फासीवादी शासन व्यवस्था कभी भी मेहनतकश वर्ग की हितैषी नहीं हो सकती। वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियां भी इस तथ्य को साबित करती हैं परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज इस सरकार की साम्प्रदायिक नीतियों को हमारे मजदूर वर्ग के साथियों का व्यापक समर्थन हासिल है। चाहे बात राम मंदिर की हो या कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की हो, अल्पसंख्यकों के साथ किये जा रहे व्यवहार की हो या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सवाल हों, मजदूरों सहित आम बहुसंख्यक आबादी का समर्थन सरकार को हासिल है। इसीलिए चुनाव में न केवल भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता बल्कि बड़ी संख्या में वामपंथी श्रमिक संगठनों के लोग भी भाजपा को वोट दे आते हैं। इसलिए हमें आत्मालोचनात्मक रूप से अपनी रणनीति और कार्यनीति पर विचार करना चहिये। श्रमिक संगठन के आन्दोलन को वेतन भत्ते की लड़ाई अर्थात अर्थवाद से बाहर निकालते हुए व्यापक राजनातिक परिवर्तन के लिए तैयार करना होगा। यह वह मुश्किल काम है जो हमने आरम्भ में तो बहुत किया लेकिन बाद में भुलाते गए अर्थात– मजदूर वर्ग का राजनीतिकरण। अपनी कतारों में राजनातिक चेतना और वर्गीय प्रतिबद्धता उत्पन्न किये बिना हम किसी क्रान्तिकारी परिवर्तन के बारे में सोच भी नहीं सकते। आज कुछ आर्थिक मुद्दों को लेकर टोकन आधार पर राष्ट्रीय आह्वान करने से काम नहीं चलने वाला है बल्कि एक निरंतर, जुझारू, समाजवादी चेतना से लेस समाज को बुनियादी रूप से बदलने वाले सतत मजदूर आन्दोलन की जरूरत है। जाहिर है, यह काम समाज की चेतना को बदले बिना संभव नहीं है।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 7 – 13 मई, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 5.5.2023

भाकपा, भाकपा (मा) की विजयवाड़ा में संयुक्त बैठक

भाजपा की जन विरोधी, देश विरोधी नीतियों के खिलाफ राजनीतिक एकता

राम नरसिम्हा राव

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा) ने संयुक्त रूप से बी.आर. अम्बेडकर जयंती के अवसर पर ''प्रचार भेरी'' सभा का आयोजन 14 अप्रैल 2023 को विजयवाड़ा स्थित एम.बी. विज्ञान केंद्रम में किया। प्रचार भेरी, अर्थात प्रचार अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य भाजपा नीत सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनगण को अवगत कराना और इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनगण को लामबंद करना है। प्रचार भेरी सभा ''देश बचाओ और जन विरोधी, निरंकुश, सांप्रदायिक भाजपा को अपदस्थ करो'' के नारे के साथ की गई थी।

सभा की अध्यक्षता दोनों पार्टियों के राज्य सचिव सदस्यों दोनपुदी शंकर और बाबू राव ने संयुक्त रूप से की।

सभा में भाकपा और भाकपा (मा) के राष्ट्रीय सचिव सदस्य बिनोय विश्वम और पोलित ब्यूरो सदस्य प्रकाश करात दोनों ने एक आवाज में कहा, ''2024 के चुनावों में भाजपा को अपदस्थ कर दिया जाएगा यदि धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक और वाम ताकतें एकजुट हों और इसके लिए संयुक्त संघर्ष समय की की जरूरत है और राजनीतिक पार्टियों को अपने राज्यों के मौजूदा राजनीति परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एकजुट होना होगा।'' नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार हिन्दुत्व कॉरपोरेट गठजोड़ कायम करने के लिए राज्य में बड़े कॉरपोरेट घरानों को बढ़ावा दे रही है और इसलिए इस प्रवृति के विरूद्ध संयुक्त कम्युनिस्ट आंदोलनों की जरूरत है।

भाकपा राष्ट्रीय सचिवमंडल बिनोय विश्वम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंध्रप्रदेश आते हुए मुझे तेलंगाना के सशस्त्र आंदोलन एवं राजेश्वर राव, मकीनेनी बासव पुन्नैया, पुचलापल्ली सुन्दरैया जैसे कम्युनिस्ट नेताओं के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलनों की याद आनी शुरू हो गई।

उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट जिस विचारधारा का अनुसरण करते हैं वह विचारधारा उस हिन्दुत्व विचारधारा से अलग है जिसका अनुसरण नरेन्द्र मोदी करते हैं। चूंकि हम वाम दल हैं, हम सभी मार्क्सवाद के प्रति प्रतिबद्ध हैं मार्क्सवाद के माध्यम से हमें दुनिया के घटनाक्रमों की पूरी जानकारी है। बिनोय विश्वम ने कहा, मार्क्सवाद एक विज्ञान है और इसे कम्युनिस्ट घोषणापत्र में समझाया गया है।

कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले कहा कि पूंजी सभी को अपना गुलाम बना देगी। जैसे पूंजी विजयी हो रही है प्रत्येक कर्मचारी और लेखक पूंजी का गुलाम बन रहा है। इसे साफ–साफ मोदी के शासन में देखा जा सकता है। लगभग वो अडानी जैसे कुख्यात भीमकाय कॉरपोरेट के गुलाम बन गए हैं। भाजपा नेता कई भ्रामक मामलों में बोलते हैं, लेकिन अडानी के घोटालों के बारे में चुप रहते हैं कि कैसे उसकी संपति इतने कम समय में कई गुणा बढ़ गई है।

भाकपा नेता ने आगे कहा कि भाजपा और आरएसएस के नेता अंबेडकर की विचारधारा की बात करते है। लेकिन वे कभी उनके आदर्शों को नहीं अपनाते। अंबेडकर ने साफ–साफ कहा था कि इस देश की नीति हिन्दू राष्ट्र नहीं है लेकिन मोदी इसके विपरीत काम कर रहे हैं हम निश्चित रूप से कह सकते है। कि भाजपा और आरएसएस फासीवादी विचारधारा को अपनाते हैं। उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि फासीवादी विचारधारा को केवल साम्यवाद से ही चुनौती दी जा सकती है।

कम्युनिस्ट प्रवर्तन निदेशालय, इंकम टैक्स और सीबीआई से नहीं डरते। भाकपा और भाकपा (मा) दोनों ही चुनाव आयोग के सार्टिफिकेट पर निर्भर नहीं है। वास्तव में दोनों पार्टियां आम जनता के मुद्दों पर संघर्षों को जनगण के समर्थन के माध्यम से काम कर रही हैं। प्रत्येक मामले में एकता अनिवार्य और दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां और उनके जन संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए।

भाकपा (मा) पोलित ब्यूरो सदस्य प्रकाश करात ने सभा में अपने संबोधन में कहा कि भाजपा और आरएसएस अंबेडकर को अपनाने की व्यर्थ कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह याद दिलाया कि सात दशकों से धर्मनिरपेक्ष पार्टियां संविधान की रक्षा कर रही हैं, आजाद की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने कई कुर्बानियां दी है। अम्बेडकर ने उन मूल्यों को हमारे संविधान में शामिल किया है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर एक महान व्यक्ति थे जो कि आजीवन जातिवाद के खिलाफ और सामाजिक न्याय के लिए लड़े और उन्होंने मनुस्मृति का भी विरोध किया। हमारे संविधान को जाति और सांप्रदायवाद की बुराइयों से हटाकर बनाया गया था।

भाकपा (मा) नेता ने संविधान को मनुवाद से बदलने की मोदी सरकार की कोशिशों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, हालांकि आरएसएस की स्थापना 1925 में हो गई थी फिर भी ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं लड़े। उनका निरंकुशता भरा तर्क है कि संविधान का आधार धर्मनिरपेक्षता और जनतंत्र नहीं होना चाहिए। उनकी मंशा भारत को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की है।

आरएसएस हमारे धर्मनरपेक्ष संविधान को बदलकर सांप्रदायिक और जातिवादी दस्तावेज बनाना चाहती है। हालांकि जब भी वे हमारे संविधान की शपथ लेते हैं वे इसके ढांचे को बदलने का षडयंत्र करते हैं।

आम जनता के हित में जो जन प्रतिनिधि हैं भाजपा उनकी आवाज को दबा रही है। वे ईडी, आईटी, और सीबी आई के दुरुपयोग से विपक्ष के नेताओं पर हमला कर रहे हैं।

अडानी की आय में कई गुणा वृद्धि का कारण बंदरगाह, हवाई अड्डे और बिजली परियोजनाएं हैं जो कि मोदी सरकार ने उसे सौंपी है।

प्रचार भेरी का उद्देश्य देश को बचाने के लिए जनगण को राजनीतिक रूप से जागरूक करना है। प्रकाश करात ने प्रचार भेरी कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई दी।

बिनोय विश्वम और प्रकाश करात के भाषण का तेलुगु अनुवाद प्रजाशक्ति के पूर्व सहायक संपादक एस. वेंकट राव ने किया।

इस संयुक्त सभा में भाकपा और भाकपा (मा) के राष्ट्रीय, राज्य, नगर नेता भाकपा आंध्रप्रदेश राज्य सचिव के. राम कृष्णा, भाकपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य पी. दुर्गा भवानी, भाकपा नगर सचिव जी. कोटेश्वर राव, व अनय पार्टी नेता लंका दुर्गा राव, नक्का वीरभद्र राव, पनचदराला दर्गांबा, भाकपा (मा) राज्य सचिव वी. श्रीनिवास राव, केंद्रीय समिति सदस्य पीत्र मधु, भाकपा (मा) राज्य कार्यकारिणी सदस्य के. श्रीदेवी, भाकपा (मा) एन.टी.आर. जिला सचिव डी.वी. कृष्णा आदि के अलावा दोनों पार्टियां के जनसंगठनों के नेता एवं कार्यकर्ता शामिल थे।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक:** रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.